RNI No. UPHIN/2000/3766 ISSN No. 2581-3528 ₹:20

केशव संवाद

माघ-फाल्गुन विक्रम सम्वत् 2078 (फरवरी -2022)

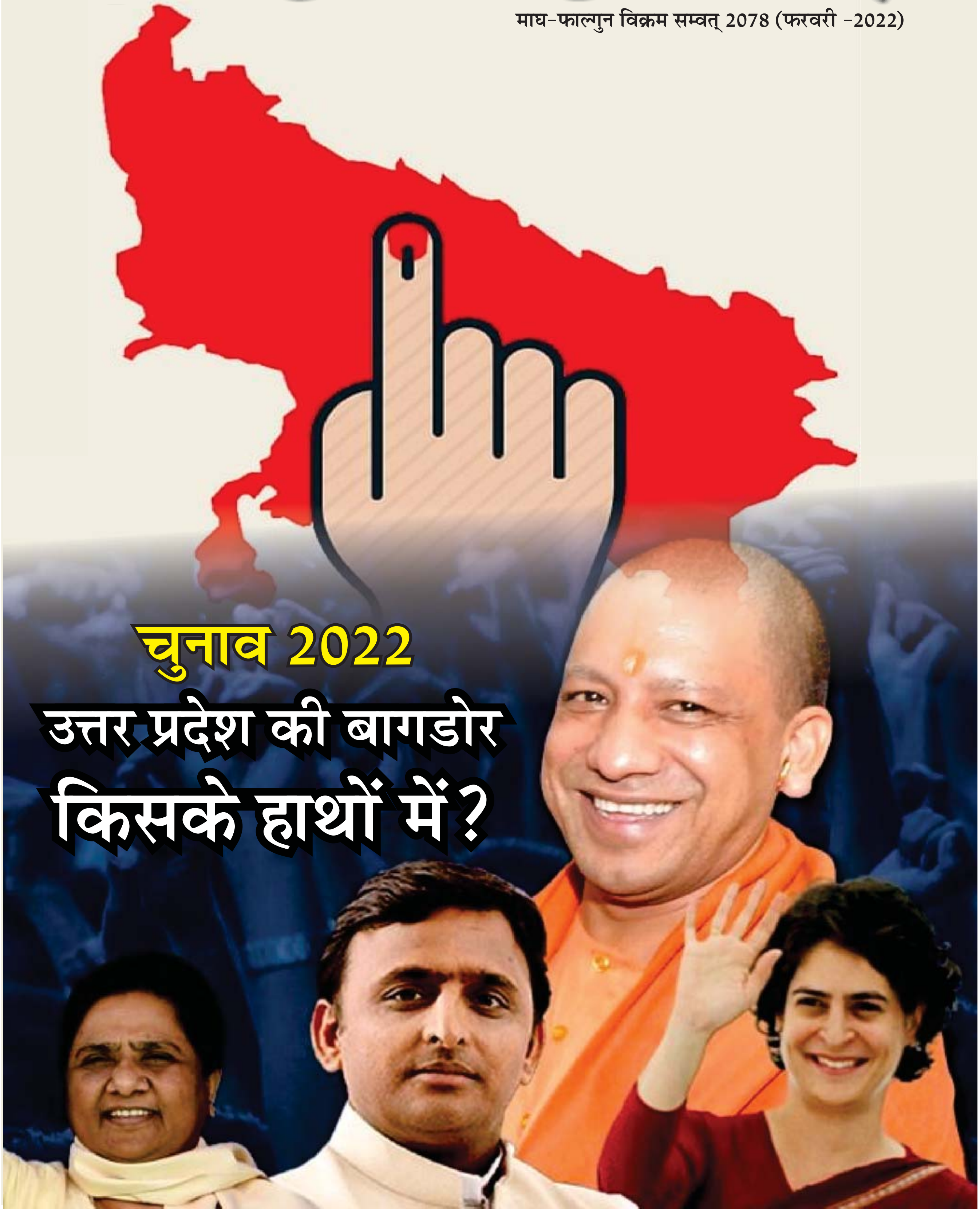

चुनाव 2022

उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में ?

फरवरी 2022, माघ-फाल्गुन विक्रम सम्वत् 2078
हिन्दी पंचांग

रविवार	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
त्रयोदशी (कृष्ण) 13 30	चतुर्दशी (कृष्ण) 14 31	● अमावस्या 15 1	प्रतिपदा (शुक्ल) 1,2 2	तृतीया (शुक्ल) 3 3	चतुर्थी (शुक्ल) 4 4	पंचमी (शुक्ल) 5 5
षष्ठी (शुक्ल) 6 6	सप्तमी (शुक्ल) 7 7	अष्टमी (शुक्ल) 8 8	अष्टमी (शुक्ल) 8 9	नवमी (शुक्ल) 9 10	दशमी (शुक्ल) 10 11	एकादशी (शुक्ल) 11 12
द्वादशी (शुक्ल) 12 13	त्रयोदशी (शुक्ल) 13 14	चतुर्दशी (शुक्ल) 14 15	○ पूर्णिमा 15 16	प्रतिपदा (कृष्ण) 1 17	द्वितीया (कृष्ण) 2 18	तृतीया (कृष्ण) 3 19
चतुर्थी (कृष्ण) 4 20	पंचमी (कृष्ण) 5 21	षष्ठी (कृष्ण) 6 22	सप्तमी (कृष्ण) 7 23	अष्टमी (कृष्ण) 8 24	नवमी (कृष्ण) 9 25	दशमी (कृष्ण) 10 26
एकादशी (कृष्ण) 11,12 27	त्रयोदशी (कृष्ण) 13 28	चतुर्दशी (कृष्ण) 14 1	● अमावस्या 15 2	प्रतिपदा (शुक्ल) 1 3	द्वितीया (शुक्ल) 2 4	तृतीया (शुक्ल) 3 5

मौनी अमावस
फरवरी 1, 2022, मंगलवार
माघ, कृष्ण अमावस्या

वसन्त पञ्चमी
फरवरी 5, 2022, शनिवार
माघ, शुक्ल पञ्चमी

रथ सप्तमी
फरवरी 7, 2022, सोमवार
माघ, शुक्ल सप्तमी

भीष्म अष्टमी
फरवरी 8, 2022, मंगलवार
माघ, शुक्ल अष्टमी

जया एकादशी
फरवरी 12, 2022, शनिवार
माघ, शुक्ल एकादशी

कुम्भ संक्रान्ति
फरवरी 13, 2022, रविवार
सूर्य का मकर से कुम्भ राशि में प्रवेश

माघ पूर्णिमा
फरवरी 16, 2022, बुधवार
माघ, शुक्ल पूर्णिमा

विजया एकादशी
फरवरी 26, 2022, शनिवार
फाल्गुन, कृष्ण एकादशी

गौण विजया एकादशी
फरवरी 27, 2022, रविवार
फाल्गुन, कृष्ण एकादशी

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

फरवरी, 2022
वर्ष : 22 अंक : 02

अणंज कुमार त्यागी
अध्यक्ष
प्रे. शो. सं. न्यास

संपादक
कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

संपादक मंडल
डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र,
डॉ. नीलम कुमारी, रामकुमार शर्मा
डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी
अनुपमा अग्रवाल

पृष्ठ संयोजन
वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301
फोन नं. 0120 4565851, 2400335
ईमेल : keshavsamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.prernanews.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन 105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

हिन्दुत्व का सीधा संबंध राष्ट्र के पुनर्निर्माण से –प्रो. अनिल निगम.....05

उत्तर प्रदेश में सुशासन हेतु चुनाव-2022 - अशोक कुमार सिन्हा.06

लोग दूरदर्शी क्यों नहीं - नरेन्द्र भदौरिया.......08

विकास का योगी प्रतिमान - प्रो. ए.पी. तिवारी....10

चतुर्थ औद्योगिक क्रांति भारत के लिए... - प्रो. अखिलेश मिश्र..12

समृद्ध विरासत की पावन भूमि उत्तर प्रदेश - प्रो. हरेन्द्र सिंह.........14

आपदा काल में यूपी सरकार का कुशल प्रबंधन - अनुपमा अग्रवाल....16

यूपी के रण में कानून व्यवस्था पर जनता ... - अनीता चौधरी.......18

महिलाओं को सशक्त बनाता मिशन शक्ति अभियान - डॉ. नीलम कुमारी....20

साक्षात्कार - बिमला बाथम - नेहा कक्कड़............22

योगी सरकार में कृषि विकास व किसानों का सम्मान - मृत्युंजय दीक्षित.......24

लो फिर बसंत आया, मन में उमंग छाया - नीलम भागी............26

असहिष्णु वैश्विक बौद्धिक सक्रियतावाद और... - डॉ. अक्षय कु. सिंह...27

आधी आबादी की भागीदारी - मोनिका चौहान........28

क्या अब मथुरा की बारी है? - रंजना मिश्रा............29

स्वास्थ्य सुविधाओं का सुशासन - डॉ. विनीत उत्पल......30

दिनचर्या - डॉ. सुनेत्री सिंह........31

उत्तर प्रदेश 2017 से पहले और बाद - डॉ.निर्भय प्रताप सिंह.32

पत्रिका के जनवरी अंक की समीक्षा - डॉ. प्रियंका सिंह......35

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया,'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail-com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय..

भारत के राष्ट्रीय चिंतन के मूल में वह सनातन आध्यात्मिक संस्कृति है जिसने दुनिया को न केवल सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव एवं विश्वबन्धुता सिखायी है अपितु, विश्वकल्याण को अपना गरिमामय लक्ष्य भी बनाया है। राम, कृष्ण और शिव इस विश्वकल्याणकारी संस्कृति के आराध्य होने से कहीं बढ़कर भारतीयों के रोम-रोम में संचारित होती प्राणवायु हैं। सौभाग्य से संस्कृति के इन स्तम्भों के केंद्र विधानसभा चुनावों के लिए तैयार उत्तर प्रदेश की अयोध्या, मथुरा एवं काशी नगरियों में हैं। आज भी जन-जन के शिवमय (कल्याण) होने का मन्त्र श्रीराम की करनी और श्रीकृष्ण की कथनी के समैक्य में निहित है। स्वाभाविक रूप से 23-करोड़ प्रदेशवासी एक ऐसे शासन की आकांक्षा रखते हैं जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को केंद्र में रखकर आधुनिक, समृद्ध एवं सशक्त उत्तर प्रदेश निर्मित करने के लक्ष्य को समर्पित हो। यद्यपि हजारों-लाखों वर्षों के इतिहास में अनेकों शासन व्यवस्थाएं विकसित हुईं, तथापि उनको कसौटी पर कसने का मानक आजतक भी रामराज्य ही है। अतः उत्तर-प्रदेश एक ऐसे शासन की राह तक रहा है जो आधुनिकता एवं व्यावहरिकता के साथ ही रामराज्य की निम्नलिखित व्यवस्थाओं को जीवंत कर दिखाने में सक्षम हो।

नहीं दरिद्र कोउ, दुखी न दीना। नहीं कोउ अबुध, न लक्षन हीना।।

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।

सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।

अर्थात एक ऐसा शासन जो भारतीय सनातन मूल्यों एवं संस्कृति आधारित ऐसा प्रदेश निर्मित करने के लिए संकल्पित हो जो- भय, भूख, गरीबी, वर्ग-विभेद एवं भ्रष्टाचार से मुक्त हो; जनमानस की सुरक्षा, प्रतिष्ठा एवं चिकित्सा (शारीरिक एवं मानसिक) सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हो; प्राकृतिक एवं जन-निर्मित आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, कोरोना जैसी महामारी, आतंकवाद एवं अलगाववाद से पार पाने में सक्षम हो; प्रदेश वासियों को व्यवाहरिक एवं रोजगारपरक कौशल यथा कला, शिल्प, वास्तु, व्यवसाय, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, विश्वस्तरीय तकनीक एवं प्रशिक्षण द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दूरदृष्टि से युक्त हो। शासन की बागडोर उन हाथों में हो; जिनके चिंतन-मनन के केंद्र में परिवार, रिश्तेदार अथवा स्वयं नहीं वरन् उत्तर-प्रदेश की तेईस करोड़ जनता हो, जिनके लिए शासन जनसेवा एवं जीवनमूल्य स्थापित करने का माध्यम हो, जिनमें राज्य एवं समाज से लेने नहीं अपितु, 'तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ' की भावना हो, जो ट्रस्टीशिप के सामाजिक-आर्थिक दर्शन, "जो भी हमारे पास है वह देश एवं समाज का है, उन्हीं की बेहतरी के लिए है और उन्हीं को लौटने को है" का मनसा, वाचा, कर्मणा पालन करने वाले हों। आइये ऐसी सरकार चुनें जो रामराज्य के अनुरूप शिक्षा-न्याय-दंड व्यवस्था स्थापित कर परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त एवं समृद्ध कर देश-दुनिया को वही लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर सके।

संपादक

ISSN No. 2581-3528

हिंदुत्व का सीधा संबंध राष्ट्र के पुनर्निर्माण से

प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार निगम

"ऐक्यं बलं समाजस्य तदभावे से दुर्बलः
तस्मादैक्यं प्रशंसन्ति दृढं राष्ट्रहितैषिणः।"

कहने का आशय है कि अगर अकेला व्यक्ति खड़ा होता है तो राष्ट्र दुर्बल होता है। पर जब लोगों में एकता आ जाती है तो राष्ट्र का हित होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शायद इसी लक्ष्य को लेकर प्रदेश में हिंदुत्व और विकास का परचम लहराने का प्रयास किया है। यहां यह समझने की आवश्यकता है कि मोदी और योगी का हिंदुत्व संकुचित नहीं बल्कि उसका स्वरूप व्यापक एवं विराट है। अगर हम उनके कार्यों का आंकलन करें तो पता चलता है कि इसका सीधा संबंध राष्ट्र के विकास और पुर्निर्माण से है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर का निर्माण, मथुरा और चित्रकूट धाम में विकास संबंधी कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करना महज धार्मिक स्थलों का पुनुरुद्धार नहीं बल्कि इसके माध्यम से इन क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करना प्रमुख लक्ष्य रहा है। पिछले वर्ष अक्तूबर से अब तक योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेढ़ दर्जन से अधिक बड़े कार्यक्रमों का नेतृत्व किया जिनमें अयोध्या में देव दीपावली, केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य, मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास और काशी कॉरिडोर का उद्घाटन प्रमुख कार्यक्रम रहे।

एक अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, 'अब अगर अगली कार सेवा हुई तो गोलियां नहीं चलेंगी, रामभक्तों और कृष्ण भक्तों पर पुष्प वर्षा होगी' और समय–समय पर वे जनता को जिन्ना, औरंगजेब और गजनी की याद भी दिलाते रहे। मोदी और योगी देश और उत्तर प्रदेश में प्रायः रामराज्य लाने की बात करते रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलकर इसे पांच प्रमुख प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्यों में शामिल करेंगे। गांधी जी ने जिस रामराज्य का उल्लेख किया था, उस रामराज्य का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेंगे। 22 हजार करोड़ की लागत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, नौ हजार करोड़ का एम्स अस्पताल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास, गौतमबुद्धनगर जिले में जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या में एयरपोर्ट इत्यादि विकास की ऐसी योजनाएं हैं जो इस दिशा में किए जाने वाले सार्थक प्रयास हैं। इन विभिन्न परियोजनाओं के सहारे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

गौरतलब है उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। कोरोना वैश्विक महामारी की तीसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सियासत की जुबानी जंग छिड़ी हुई है। विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की हिंदुत्व की धार को कमजोर करने और खुद को हिंदुत्व के रंग का चोला ओढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है।

हालांकि इस समय कांग्रेस पार्टी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कमजोर नेतृत्व के चलते इतिहास में पहली बार कांग्रेस में गांधी परिवार की राजनीतिक प्रासंगिकता पर ही सवाल हो रहे हैं। हालांकि पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब मंदिरों में जाकर न केवल माथा टेक रहे हैं, बल्कि वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं वे हिंदू विरोधी नहीं हैं। उन्होंने हिंदुत्व की उल्टी–सीधी व्याख्या कर पार्टी को हास्यास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। कभी मुस्लिमों के बीच प्रचंड पकड़ रखने वाली कांग्रेस से यह समुदाय भी दूर खड़ा नजर आ रहा है।

समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी जातिगत राजनीति को धार देने के उद्देश्य से अत्यंत विवादास्पद बयान दे डाला। मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्होंने भारत के विभाजन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार मो. अली जिन्ना के जिन्न को फिर से जिंदा कर दिया। अखिलेश ने जिन्ना की तुलना राष्ट्रवाद के पर्याय सरदार पटेल से करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। उनका भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक अन्य नेता ओमप्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो देश का विभाजन नहीं होता।

विभिन्न राजनेताओं की अनर्गल बयानबाजी इस बात का प्रतीक है कि उनके अंदर जबर्दस्त बेचैनी एवं बौखलाहट है। वे हिंदुत्व एवं विकास के विराट वैभव और लोगों में उसकी स्वीकारोक्ति से परेशान एवं हैरान हैं। यही कारण है कि वे समाज में जातीय विद्वेष, हिंसा, वैमनस्य और घृणा फैलाने वाली बयानबाजी कर समाज और राष्ट्र को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जनता अत्यंत सजग, सचेत और जागरूक हो चुकी है, इसलिए उसको बहलाकर अपना उल्लू सीधा करना अब इतना सहज नहीं होगा।

(लेखक, आईएमएस, गाजियाबाद में पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय के चेयरपर्सन हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

उत्तर प्रदेश में सुशासन हेतु चुनाव - 2022

अशोक कुमार सिन्हा

स्वतंत्रता संग्राम का यह प्रदेश सबसे प्रभावशाली क्षेत्र रहा है। भारतीय संस्कृति की विराट झांकी इस प्रदेश में मिलती है।

प्रयाग, चित्रकूट, अयोध्या, काशी, मथुरा, श्रावस्ती, कुशीनगर, गोरक्षधाम, मेरठ, नोएडा (हस्तिनापुर), आगरा, कन्नौज और लखनऊ जैसे ख्याति प्राप्त नगरों का यह विशाल राज्य अपनी व्यवस्था के लिए वर्ष 2022 में नई सरकार के गठन के लिए नई सरकार चुनने जा रहा है। 2,40,928 वर्ग किमी के विस्तृत क्षेत्रफल में कुल 75 जनपदों में विभाजित है। उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार और नेपाल इसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती, गोमती, घाघरा (सरयू) बेतवा और केन नदियों से अभिसिंचित यह प्रदेश विशाल कृषि क्षेत्र सहित 21,833 वर्ग किमी वनावरण से आच्छादित है। लोकसभा के 80 सांसद यहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल 404 विधानसभा सदस्य, 100 विधान परिषद सदस्य, 31 राज्यसभा सदस्य यहां से चुने जाते हैं। 2022 में 18वीं विधानसभा का चुनाव होगा क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त होने जा रहा है। विगत चुनाव में 14.66 करोड़ मतदाताओं की संख्या गणना की गई थी। 61 प्रतिशत मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश के साथ–साथ पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा, मणिपुर में भी चुनाव होंगे परन्तु सभी राजनीतिज्ञों की नजर उत्तर प्रदेश पर रहेगी क्योंकि राजनैतिक विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली की केन्द्रीय सरकार के बनने में सर्वाधिक महत्व उत्तर प्रदेश की सरकार पर निर्भर करता है। विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। समाजवादी गठबन्धन को 54 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली थीं। प्रदेश की साक्षरता दर 67. 7 प्रतिशत है परन्तु राजनैतिक चेतना प्रबल है। कुल 1,06,774 गांवों में बसा यह प्रदेश नई चुनाव के आहट से सजग हो गया है।

उत्तर प्रदेश ने चौदह में से मोदी सहित नौ प्रधानमंत्री दे कर अपनी राजनैतिक चेतना का परिचय दिया है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध ने अपने जन्म हेतु इसी धरा को चुना।

फरवरी से मार्च 2022 के मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल (नेता अनुप्रिया पटेल) व, निषाद पार्टी (नेता प्रवीण कुमार निषाद) एक तरफ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बी.जे. पी. अन्य दलों से भी गठबन्धन बनाने के लिये प्रयासरत है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी (नेता अखिलेश यादव) राष्ट्रीय लोकदल (नेता जयंत चौधरी), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (नेता ओम प्रकाश राजभर) तथा राष्ट्रीय जनता दल (नेता तेजस्वी यादव) एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और दलों को भी गठबन्धन में सम्मिलित करने के प्रयास जारी हैं। बहुजन समाज पार्टी खामोशी से अकेले चुनाव लडने को तैयार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (नेता प्रियंका गांधी वाड्रा), तृणमूल कांग्रेस (नेता नीरज राय), शिवसेना (नेता उद्धव ठाकरे), भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (नेता गिरीश शर्मा), भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (नेता हीरा लाल यादव), जनतादल युनाइटेड, जनतादल लोक तान्त्रिक (नेता रघुराज प्रताप सिंह), आल इण्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) नेता शौकत अली व ओवैसी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है। AIMIM ने अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अपना दल (नेता कृष्णा पटेल), जनाधिकार पार्टी (नेता बाबू सिंह कुशवाहा), विकासशील इंसान पार्टी (नेता मुकेश साहनी), लोक जनशक्ति पार्टी (नेता चिराग पासवान), आजाद समाज पार्टी (नेता चन्द्रशेखर आजाद रावण) भी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश पूर्वांचल, मध्य क्षेत्र, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उ.प्र. के जाट बहुल क्षेत्र में विभाजित है। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही 164 विधान सभा सीटें और 33 प्रतिशत मतदाता हैं।

प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी दल, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मध्य में हैं। इनकी ताकत व संगठन क्षमता भी इसी क्रम में है। नरेन्द्र मोदी व योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बी.जे.पी. का चुनाव अभियान जहां तेजी से प्रारम्भ हो गया है, वहीं अखिलेश यादव जनरथ यात्रा पूरी कर चुके हैं। प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही हैं। प्रचार में बहुजन समाज पार्टी जातिगत सम्मेलनों में व्यस्त हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुल 8 विधानसभा सीटें क्रमशः वाराणसी उत्तरी, वाराणसी कैण्टोनमेन्द, रोहनियाँ, शिवपुर, सबरी, पिण्डरा, अजगरा और वाराणसी दक्षिणी हैं। विगत चुनाव में अधिकतर सीटों बी.जे.पी. के हाथ लगी थीं।

विगत 2017 में कुल 7 चरणों में चुनाव हुये थे। इस वर्ष चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली हैं। विगत चुनाव में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (बी.जे.पी., अपना दल (सोनेलाल पटेल) सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) ने कुल 325 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और 41.35 प्रतिशत मत प्राप्त हुये थे। गत चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 28.7 प्रतिशत मत प्राप्त कर 54 सीटें जीती थी जिनके 47 समाजवादी पार्टी ने व 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बहुजन समाज पार्टी को 22.23 प्रतिशत मत व 19 सीटें मिली थीं। राष्ट्रीय लोकदल को 1.78 प्रतिशत मत व एक सीट मिली थी। निषाद पार्टी को एक व निर्दलीयों को तीन सीटें प्राप्त हुई थी। यद्यपि आगामी चुनावों में समीकरण बदले हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उनकी लोकप्रियता भारत के स्तर पर बढ़ी है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव जीतना चाहती है। मुख्य मुकाबला इन्ही दो दलों के मध्य है। योगी जी ने डबल इंजन की सरकार बनाकर प्रदेश में वास्तविक प्रगति के आंकड़ों में वृद्धि की है। पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन कराया है और प्रयागराज से मेरठ एक्सप्रेस–वे का शिलान्यास कर रहे है।

निःसंदेह अपराध दर में गिरावट आई है। डकैती, लूट, हत्या दंगा, बालात्कार और बलवों में कमी आई है। 59 नये थाने, 29 नई चौकियां, 4 नई महिला थाने और आर्थिक अपराध शाखा के 4, विजिलेंस के 10, साइबर क्राइम के 16 थाने व 59 नये अग्निशमन केन्द्र खुले हैं। बड़े

अपराधी जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, संजय सिंह व दबंग नेता, आजम खां जेल में हैं व सम्पत्तियाँ कब्जे में ली गई हैं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति से समाज पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हुआ है। महिला सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति के अच्छे परिणाम आये है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल में उत्तम व्यवस्था के कारण योगी की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। 30 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है या हो रही है। 2 नये एम्स (गोरखपुर व रायबरेली) में संचालित हो गये हैं। ऑक्सीजन प्लाटों की स्थापना से अब भरपूर ऑक्सीजन प्रदेश में उपलब्ध है।

प्रदेश में एक्सप्रेस वे व हाइवे का संजाल तीव्र गति से विकसित होने के कारण व 5 नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की व 17 नये एयरपोर्ट के निर्माण प्रक्रिया से प्रदेश पूंजी निवेश के क्षेत्र में देश में 14वें स्थान से प्रोन्नत हो कर दूसरे स्थान पर आया है। केवल कोरोना काल में 56000 करोड़ का पूजी निवेश हो गया। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट व डेटा सेन्टर पार्क स्थापित हो रहे है। सैन्य उपकरणों हेतु डिफेंस कॉरिडोर ने नई आशा जगाई है। ग्रेटर नोएडा में एशिया का सबसे सुन्दर जेवर एयरपोर्ट बनाने व फिल्म सिटी की घोषणा से राष्ट्रीय फिल्म उद्योग को यू.पी. में नई संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। योगी सरकार का दावा है कि सर्वाधिक चीनी उत्पादन एवं गन्ना मूल्य भुगतान, नई मिलों का संचालन, गोरखपुर खाद कारखाना स्थापित होने के कारण प्रगति को नया आयाम मिला है। वर्ष 1972 से लम्बित सरयू नहर व बांध योजना पूर्ण होने से पूर्वांचल के 30 जिलों को लाभ मिला है। 11 अन्य सिंचाई परियोजना पूर्ण हुई है।

केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन योजना, उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन, ग्रामीण सड़क योजना, शौचालय योजना, स्वच्छता मिशन ने प्रगति को और तेज कर दिया है।

आज उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन में देश में प्रथम स्थान पर हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान, माता विंध्यवासिनी व शकुम्भरी देवी का विकास कार्य अद्वितीय रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना सफल सिद्ध हुई है। विद्युत उत्पादन में जिला मुख्यालय में 24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली पहुंची है तथा 1 लाख 21 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा हुआ है। शिक्षा, रोजगार और महंगाई के मोर्चे पर वर्तमान सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ा है। सांस्कृतिक संरक्षण व राष्ट्रवाद के क्षेत्र में कल्पनातीत कार्य हुए हैं जिसमें संभवतः आजादी के 70 वर्षों के बाद प्रदेश के बहुसंख्यक समाज को हार्दिक शांति व संतोष हुआ है और उनकी घोर निराशा, उच्च मनोबल में परिवर्तित हुई है। धारा 370 और 35ए की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़े गौरव ने सभी जनता का मस्तक गर्व से ऊंचा उठा दिया है। यह असंभव कार्य संभव बना कर बीजेपी ने 'जो कहा उसे पूरा किया का वचन निभाया है। अल्पसंख्यक समाज में भी दंगों पर काबू करना, बिना भेदभाव के उनको सुविधाओं को उपलब्ध कराने व तीन तलाक की प्रक्रिया में सुधार लाने के कारण बीजेपी के प्रति निकटता को बढ़ाया है। यद्यपि असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश में सघन प्रचार के कारण मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ा है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय का रणनीतिक वोट केवल उन्हें ही मिलेगा परंतु ऐसा कम होगा। वोट तो सभी को बटेंगे। हो सकता है कि आगामी चुनाव राजनीति को कुछ नया आयाम दे।

समाजवादी पार्टी सहित सभी पार्टियों को योगी आदित्यनाथ और मोदी नेतृत्व का विकल्प प्रस्तुत करने में दशकों लगेंगे। अभी तो प्रदेश की जनता बीजेपी से बहुत नाराज नहीं दिखती है तथा समस्त वोटर सर्वे योगी को तथा बीजेपी को प्रथम स्थान पर ही दिखा रहे हैं। योगी की कर्मठता, ईमानदारी तथा बेवाकी सभी विपक्षियों पर भारी है। गठबंधन तो विगत चुनाव में भी सफल नहीं हुआ था और आज तो स्थिति और सुथरी दिखाई पड़ती है। किसान आंदोलन, शिक्षक भर्ती, प्रश्नपत्र आउट हो जाने व लखीमपुरखीरी किसान आंदोलन का डैमेज कंट्रोल तेजी से संभव बनाया जा रहा है। मोदी जी पर और योगी जी पर जनता का आज भी विश्वास कायम है और इनके आसपास अभी कोई पहुंचता दिखाई नहीं पड़ रहा है। चुनाव नजदीक आते तथा घोषणा होते ही बीजेपी की रणनीति व संगठन क्षमता और बढने वाली है। विपक्षियों के सभी पत्ते खुल चुके हैं अतः नया कुछ नहीं आने वाला है। जातीय गणित साधना सभी के लिए टेढ़ी खीर है। इस चुनाव में भाजपा के सामने संगठन बल बढ़ाकर प्रदर्शन दोहराने और विपक्षियों के दमखम की अग्नि परीक्षा है। अखिलेश के साथ पश्चिम में जयंत की चौधराहट कायम रहे यह मुश्किल लग रहा है। जयंत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पश्चिम में जाट, गुर्जर और मुसलमान एकता रालोद की पाला बदल नीति से कमजोर हुई है और रालोद की साख गिरी है। यद्यपि विरोधी दल प्रचार कर रहे हैं कि योगी के विकास का दावा थोथा है। मोदी ने वाराणसी में भाजपा के 13 मुख्यमंत्रियों की बैठक में युवा संगठन की बैठक में व संगठन की बैठक में स्पष्ट किया है कि इस वर्ष चुनाव में रिपोर्ट कार्ड व लोकप्रियता के आधार पर विधायकों को टिकट मिलेंगे। विधायक सिफारिश से दूर रहें और ऐसा काम करें कि जनता आपको फिर चुने। इस बात की संभावना बढ़ रही है कि यूपी में सौ से डेढ़ सौ वर्तमान विधायकों के टिकट कटेंगे। यदि भाजपा यह हिम्मत दिखाती है तो उसकी जीत पक्की हो सकती है।

(लेखक लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान के निदेशक हैं)

लोग दूरदर्शी क्यों नहीं

नरेन्द्र भदौरिया

राजनीति ने उत्तर प्रदेश में बड़ी करवट ली है। बहुदलीय राजनीति ने अचानक ऐसा परिवर्तन दर्शाया है मानो दो दलीय राजनीति का समय बस आने ही वाला है। इसमें मुख्य योगदान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का है यह कह देना ठीक नहीं है। राजनीतिक विवेचक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बात भी यही है कि राज्य की जनता का मानस ऐसा हो रहा है। यह किस दल के पक्ष में जाएगा यह तपाक से कह देना भी ठीक नहीं है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक और लक्षण बहुत चकित कर रहा है। चुनाव की देहरी पर खड़े 70 साल पार के नेता अचानक अकुलाहट दर्शाने लगे हैं। इनकी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि इनकी सन्ततियां अपने लिए सुरक्षित ठौर नहीं बना पा रही हैं। चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब परिणाम लगभग एक तरफा आने के संकेत मिल रहे हैं। फिर भी दो दलीय प्रभुत्व की आहट साफ हो चुकी है। ऐसी दशा में दोनों दल बहुत सोच समझ कर स्वच्छ छवि के प्रत्याशी ला सकते हैं। यह साहस भाजपा और सपा के नेतृत्व ने दिखाया तो बूढ़े और घटिया नेताओं को बलात नेपथ्य में धकेला जा सकता है। सन् 2022 की नयी विधानसभा में उमंगों से भरे नये विधायक चुनकर आने दिये गये तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन जाएगा जहां राजनीति की नयी फसल लहलहा सकेगी। ऐसा सच में हो पाएगा। इसमें सन्देह अवश्य है। क्योंकि दोनों प्रभावी दलों के भीतर जमे बूढ़े इतने चतुर तो हैं कि बदलाव की बयार को रोक सकें। इसीलिए प्रत्याशिता में युवा वर्ग फिर ठगा अनुभव करे ऐसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक बाबा हुए थे। उन्होंने राजनीतिक दलों को परिवर्तन का एक बहुत बढ़िया मन्त्र दिया था। उनका नाम था घूरेलाल। लोग उन्हें सन्त घूरेलाल कहते थे। उनका स्थान अलीगढ़ का चिरौली नामक एक गाँव था।

बड़े सहज सन्त थे। कई शिष्य उनकी बातों की गहराई को समझ कर उनसे जुड़ते रहे। इन्हीं में एक थे बाबा तुलसीदास। यह तुलसीदास श्रीरामजी की कथा का गायन करने वाले गोस्वामी तुलसीदास से अलग थे। बाबा घूरेलाल ने इन्हें जो कुछ शिक्षा दी उसे अपनी गाँठ में बाँधकर चिरौली से ऐसा निकले कि फिर तो 20 करोड़ गुरुभक्तों के मेले संसार भर में लगा दिये।

तुलसीदास को लोग जयगुरुदेव नाम से जानते हैं। वास्तव में कोई बात बोलने से पहले वह जयगुरुदेव शब्द उच्चारण करते थे। इसलिए उनका नाम ही जयगुरुदेव पड़ गया था। जयगुरुदेव ने बाबा

ISSN No. 2581-3528

घूरेलाल की सीख को चरितार्थ करने के लिए दूरदर्शी पार्टी बनायी थी। जिसने देश के तीन आम चुनावों में अपने खूब प्रत्याशी उतारे। पर कोई जीत नहीं सका। अन्ततः पार्टी तिरोहित कर दी गयी। बाबा जयगुरुदेव इस संसार से 116 साल की अवस्था में विदा हो गये। बाबा की मृत्यु 21 मई 2012 को हुई। मथुरा में डेढ़ सौ हेक्टेयर में बाबा का बनवाया विराट आश्रम है। उनके एक कार चालक ने उन्हें मुखाग्नि दी थी।

दूरदर्शी पार्टी के घोषणापत्र की कुछ बातें बड़े काम की थीं। एक तो यह कि 60 बरस के बाद राजनीति से संन्यास लेना अनिवार्य होगा। दूसरा यह कि सांसद या विधायक बनने का अवसर किसी व्यक्ति को केवल एक बार दिया जाएगा। अन्य बातें भी थीं पर इन दो बातों के चलते कोई जमा जमाया नेता किसी दल को छोड़ कर जयगुरुदेव की पार्टी में नहीं गया। दूरदर्शी पार्टी के बेचारे टाटधारी प्रचारक देश के विभिन्न राज्यों के गांवों में सूखी रोटियां बस्ते में बाँधे धूल फाँकते रहे। उनकी पार्टी को देश की जनता ने भी गम्भीरता से नहीं लिया। बाबा तुलसीदास की याद उन लोगों को अवश्य आती है जो बूढ़े नेताओं की हर चुनाव में पलटी मारने की घुटनभरी राजनीति से उकता चुके हैं। शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व इन बूढ़ों से पल्ला झिटक कर छुड़ाने की बातें तो करता है पर लाचारी बता कर चुप हो जाता है। हर दल की साख में गहरे काले धब्बे इनमें से कई ऐसे ही नेताओं की दी हुई पहिचान है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के बीच सीधा आमना सामना हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी को जाने क्यों राज्य के बाहुबलियों ने भी इस बार मुँह उठाकर नहीं सूंघा। कहते हैं कि भाजपा ने ऐसे बाहुबलियों को ठोक पीटकर दबा दिया जो चुनाव के समय सिर उठाकर किसी एक दल की खाट सिर पर लेकर चल पड़ते थे।

दूसरे बसपा की फसल भाजपा ने काटने का पूरा प्रबन्धन कर दिया है। प्रदेश की राशन वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करके भाजपा की मोदी योगी की डबल डेकर सरकार ने गरीब मतदाताओं को खुश कर रखा है। प्रदेश की हर छोटी बड़ी नहर की सफाई तलहटी तक हुई है। बीज खाद बिजली की कमी पाँच साल नहीं होने पायी। गुण्डई को ताला लगाने में योगी सफल रहे हैं। छुटभैया नेता रुआंसे रहकर भी भाजपा के झण्डे को थामे रहे। इनकी रुसवाई भी झलकने नहीं दी गयी क्योंकि पार्टी का संगठन तन्त्र निरन्तर सक्रिय बना रहा। इससे इतना तो हुआ कि पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की पहिचान खुलकर सबको दिखायी देती रही।

उत्तर प्रदेश के किसानों को उनका गोवंश न रुलाता तो निश्चित रूप से कोई कह सकता था कि यह चुनाव एक तरफ झुक गया है। तो भी एक मायने में यहाँ एक तरह का साफ बँटवारा दिखता है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहिचान को मुस्लिम मतदाताओं के हितैषी के रूप में बनने दिया है। दूसरी ओर भाजपा जानती है कि कितना भी पीठ घुमाकर बात की जाय मुसलमान उसके पक्षधर नहीं बनना चाहते। इन दिनों कट्टरवादी मुस्लिम और मुलायम सोच वाले मुस्लिम मतदाताओं की पहिचान बहुत कठिन हो चुकी है।

इसमें दो राय नहीं कि जितना ध्रुवीकरण मुसलमान घटकों में दिखता है वैसा हिन्दुओं के जातीय या अन्य वर्गीय समूहों में नहीं है। हिन्दुओं को जातीय समूहों में बाँटे रखने की हर जुगत दूसरे राजनीतिक दल ही क्यों भाजपा के नेता भी खुलकर करते हैं। भले भाजपा को केन्द्र और राज्य में तगड़े नेतृत्व का सम्बल मिला है परन्तु राज्य में जातीय धुरन्धर नेताओं ने हिन्दुत्व के स्थान पर जातीय समूहों को सशक्त बनाने की कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ी। उनको श्रेष्ठ विचारकों के साथ जनता ने भी मौन धिक्कार लगायी तो भी कुछ अन्तर कभी नहीं पड़ा।

भाजपा का एक नारा राज्य के सामान्य मतदाताओं को बहुत रुचिकर लगा है – सोच ईमानदार काम दमदार। योगी की चाल और चेहरे को इस नारे ने सचमुच बड़ी पहिचान दी है। राज्य के दौरे पर मोदी जब भी आये इस नारे को बल दिया। योगी ने अपने को राजनीति की दुर्गन्ध से बचाये रखा। यह उनकी बड़ी पूँजी है। जो चुनाव में बड़े काम आएगी। भले ही लोगों को पूरे कार्यकाल यह लगता रहा कि पार्टी के कुछ ढीठ नेताओं के पँख बांधने की छूट बाबा को मिली होती तो पार्टी निरोगी बनकर उभर सकती थी।

भाजपा अपनी नीतियों में निर्मल दिखने में सफल रही है। पर घटिया सहयोगी नेताओं और निचले स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की गुत्थियां सुलझाने में योगी आदित्यनाथ एक और अवसर तो चाहेंगे ही। राज्य के पुलिस तन्त्र को पटरी पर लाना बहुत दुष्कर दिखता है। बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन कैसे लाये जाएंगे जब यह तन्त्र भी आईएएस संवर्ग की भाँति जातीय समीकरणों के जोड़ तोड़ से चलता आया है। भर्तियों की बहार ने शिक्षा तन्त्र को बजट का सर्वाधिक अनुत्पादक व्यय करने वाला विभाग बना दिया है। पर राज्य का शैक्षिक ढाँचा बहुत हद तक चरमराया हुआ है। अदूरदर्शी सोच राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए शाप बन चुकी है। चिकित्सा और सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में जो हुआ है वह इच्छा शक्ति तो दर्शाता है पर सार्वजनिक परिवहन के लिए लगता है अभी कुछ सोचा ही नहीं गया। हर कोई वाहन खरीदे और उलटा सीधा दौड़ाता फिरे यह तो कोई नीति नहीं हो सकती।

पिछले पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश की एक नवीन छवि उभरी है। यह राज्य पर्यटन और विशेषकर धार्मिक पर्यटन का केन्द्र बन चुका है। अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी देवी और प्रयाग की नयी चित्रावली देश और संसार भर के पर्यटकों की डायरी में छप चुकी है। उत्तर प्रदेश इस बीच कब देश का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक, दुग्ध उत्पादक और मांस निर्यातक राज्य बन गया किसी को पता ही नहीं चला।

उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की विशाल जनसंख्या में 52.6 प्रतिशत युवा हैं। जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। एक बात और उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग की सोच बदल रही है। यहां की प्रजनन दर का घटना इसी मुक्त उन्नत सोच का परिणाम है। बिहार में प्रजनन दर अभी 3.2 है तो उत्तर प्रदेश 2.6 पर आ चुकी है। बिहार में 57.8 प्रतिशत युवा हैं। केरल में केवल 40 प्रतिशत जनसंख्या युवा है। वहां प्रजनन दर सबसे कम है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

विकास का योगी प्रतिमान

प्रो. ए. पी. तिवारी

उत्तर प्रदेश (यूपी) भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का हृदय–स्थल है। लेकिन इसके बावजूद स्वाधीनता के बाद के एक लंबे कालखंड के दौरान यह विकास के मामले में गतिरोध का शिकार रहा है। इसका बड़ा कारण विकास की रणनीति में संरचनात्मक खांचा था। खेती, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास अपेक्षा के अनुरूप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पूँजी निवेश के लिए जिस तरह का परिवेश अपेक्षित था वह राजनीतिक उदासीनता के चलते साकार नहीं हो पाया। परिणामतः यूपी के समग्र विकास के लिए यहाँ उपलब्ध अंतर्जात क्षमताओं एवं संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो सका। इस पृष्ठभूमि में, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास की जिस नई रणनीति को तैयार कर बुनियादी बदलाव लाये गए हैं उनसे प्रदेश का त्वरित व संतुलित विकास हो रहा है। 'विकास का योगी प्रतिमान' मूलतः सांस्कृतिक चेतना, आर्थिक संभाव्य एवं पारदर्शी एवं कुशल प्रशासन प्रणाली पर अवलंबित है। विशेष रूप से 'इन्वेस्टर्स समिट' के बाद यूपी में आईटी, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एवं खाद्य प्रसंस्करण के विकास पर विशेष बल दिया गया है। विकास की नई रणनीति में त्वरित एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के एकीकृत प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए जिन क्षेत्रों एवं क्रियाओं पर बल दिया जा रहा है उनमें सापेक्षतया श्रम प्रधान एवं पूँजी प्रधान दोनों हैं। श्रम प्रधान में चमड़ा, कपड़ा, परिधान व खाद्य प्रसंस्करण तथा पूँजी प्रधान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोटर वाहन को सम्मिलित किया गया है। इससे रोजगार सृजन के साथ समग्र विकास हेतु आर्थिक क्रियाओं के संतुलित क्षेत्रीय छितराव पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़े जनपदों व क्षेत्रों के विकास में तेजी लाकर क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने की नीति बेहतर नतीजे दे रही है। साथ ही सूक्ष्म, लघु, मझोले उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति को लागू करने से रोजगार व आजीविका के टिकाऊ एवं गुणवत्तापूर्ण अवसरों में विस्तार से प्रदेश के आर्थिक ढांचे में विवर्तनकारी संकेत दिख रहे हैं। 'जस होत रहा वस होई' की स्थिति का परित्याग कर एक 'स्फूर्तिकारी कारोबार नीत विकास' का ऐसा परिवेश सृजित किया गया है जिसके उत्प्रेरक कारक हैं–कृषि, अवस्थापना, स्थानिक परंपरागत सामर्थ्य, कौशल विकास, नगरीय विकास एवं जवाबदेही, पारदर्शिता व मितव्ययिता पर केन्द्रित सुशासन तथा राजकोषीय अनुशासन।

अनुमान बताते हैं कि भारत के सूक्ष्म, लघु, मझोले उद्यम क्षेत्र में यूपी का हिस्सा 14.20 प्रतिशत बैठता है। इस सेक्टर के अंतर्गत कुल भारतीय निर्यात में यूपी की सापेक्षिक हिस्सेदारी इस तरह है। हस्तशिल्प (44 प्रतिशत), कालीन (39 प्रतिशत), एवं चमड़ा उत्पाद (26 प्रतिशत)। इसके दृष्टिगत विकास की नई रणनीति में इस क्षेत्र की तरक्की को प्राथमिकता दी गई है। वस्तुतः इस क्षेत्र को लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी, बाजार, वित्त एवं कौशल की नितांत आवश्यकता थी। इन्हें एमएसएमई नीति 2017 में भली–भांति समावेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्वेस्टर समिट आयोजित करने के साथ दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए योगी सरकार द्वारा पूंजी निवेश को बढ़ाने की ठोस पहल की गई है। यूपी का प्रत्येक जिला अपने परंपरागत कौशल पर केंद्रित उत्पादों के लिए जाना जाता रहा है। वस्तुतः ये उत्पाद ऐसे हैं जिन के उत्पादन में प्रदेश को न केवल तुलनात्मक लाभ प्राप्त है बल्कि इनमें विश्व के अन्य देशों के सापेक्ष स्पर्धात्मक लाभ भी प्राप्त है। इनसे जुड़े उद्योगों को सूर्योदय उद्योग (सनराइज इंडस्ट्री) की संज्ञा देना उचित होगा। इनमें उत्पादन, विकास, रोजगार एवं निर्यात की विपुल संभावनाएं हैं। योगी सरकार ने इनके संवर्धन एवं विकास के लिए 'एक जनपद–एक उत्पाद' (ओडीओपी) की महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की। ओडीओपी को एमएसएमई सेक्टर से एकीकृत किया गया है। इस तरह

ISSN No. 2581-3528

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिलों में संकुल (क्लस्टर) प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। ओडीओपी के लिए आवश्यक ऋण, कौशल विकास, उद्यमिता अप्रेंटिसशिप, भंडारण, विपणन एवं निर्यात के लिए सुविधाएं मुहैया कराने से इनकी तेज ग्रोथ के साथ रोजगार एवं आजीविका के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए आयोजित डिफेंस एक्सपो में 70 देशों के 3 हजार से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। इसमें 200 से अधिक एमओयू के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश तथा 5 लाख लोगों का रोजगार प्रक्षेपित है। वस्तुतः इससे प्रदेश में रक्षा उत्पादन का एक सबल हब उभरेगा। वहीं, इससे रक्षा एवं सिविल उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक एवं औद्योगिक अंतर्संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी जिससे समग्र औद्योगिक विकास को बल तो मिलेगा ही साथ ही बुंदेलखंड का पिछड़ापन भी दूर होगा।

प्रति व्यक्ति आय स्तर को विकास का एक सर्वमान्य संकेतक माना जाता है। यूपी की प्रति व्यक्ति आय 2015—16 में देश की प्रति व्यक्ति आय की 49.7 प्रतिशत थी जो 2020—21 में बढ़कर 50.8 प्रतिशत हो गई। यह निष्पादन दर्शाता है कि योगी सरकार में प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय स्तर एवं यूपी की प्रति व्यक्ति आय के बीच में अंतर में कमी आई है। निश्चय ही यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें निरन्तर और सुधार की आशा है। सन्दर्भित समयावधि में इसी तरह के सुधार 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों की शिक्षा, शिशु मृत्यु दर, स्वच्छता इत्यादि सामाजिक विकास के संकेतकों में भी प्रतिसाक्षित हुए हैं। अनुमान दर्शाते हैं कि कोरोना महामारी के बावजूद सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बंध में यूपी की अर्थव्यवस्था ने 2020—21 में देश में दूसरी रैंक प्राप्त कर ली है। इस तरह महाराष्ट्र के बाद यूपी की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यह सब योगी सरकार के कुशल अर्थ—प्रबन्धन संग इंफ्रास्ट्रक्चर नीत समग्र विकास के फलस्वरूप सम्भव हुआ है। विकास का योगी प्रतिमान जिन मूल तत्वों पर टिका है वे हैं— राष्ट्रवाद, सुशासन एवं सुरक्षा। धार्मिक व सांस्कृतिक महात्म्य के स्थलों यथा अयोध्या, काशी इत्यादि में उच्च कोटि की आधारभूत सुविधाओं के विकास से सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास का प्रकल्प सुदृढ़ हो रहा है। साथ ही, लोगों की रोजी—रोटी की टिकाऊ व्यवस्था में निरन्तर विस्तार आ रहा है।

विकास के योगी प्रतिमान में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी, औद्योगिक गलियारों, रक्षा गलियारा, बिजली, सिंचाई आदि को विशेष प्राथमिकता दी गयी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास, स्वच्छता, शिक्षा, पुष्टाहार, महिला व बाल कल्याण इत्यादि से सम्बंधित सुविधाओं में सतत् विस्तार एवं सुधार पर बल दिया गया है। विकास के इन रणनीतिक प्रयासों से यूपी की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना कर उसे अधिक शक्तिशाली बनाने में महती सफलता प्राप्त हुई है। भविष्य में भी इसके गतिशील परिणाम प्राप्त होने निश्चित हैं।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी की वर्ष 2020 की पहली और 2021 कि दूसरी लहर से गहरी चोट पहुंची। लेकिन जीएसटी संग्रह, रोजगार की दर एवं जीएसडीपी के अनुमान वित्त वर्ष 2021—22 में पुनः स्फूर्ति के सुस्पष्ट संकेत देते हैं। महामारी की दूसरी लहर में उद्योगों को चलाये रखने के निर्णय, संयोग से किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में महामारी से पहले महत्वपूर्ण समर्थन तथा किसानों को निरन्तर किश्तों का भुगतान, पलायित मजदूरों की स्किल मैपिंग कर ओडीओपी व मनरेगा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के प्रयासों तथा गरीबों व मजदूरों को निःशुल्क राशन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था चल पड़ी है। आगामी वित्त वर्ष में यह तीव्र विकास का प्रदर्शन कर सकती है।

(लेखक विकास मामलों के जानकार वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं) ■

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं केशव संवाद को सोशल मीडिया पर FOLLOW करें।

केशव संवाद

FACEBOOK

Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

ISSN No. 2581-3528

चतुर्थ औद्योगिक क्रांति: भारत के लिए चुनौतियां एवं संभावनाएं

प्रो. (डॉ.) अखिलेश मिश्र

विश्व आर्थिक मंच के तत्कालीन अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाब (Klaus Schwab) द्वारा लिखित पुस्तक "The Fourth Industrial Revolution (2016)" में दावा किया गया कि डिजिटाईजेशन, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, औगुमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी के बढ़ते सामान्य अनुप्रयोग के कारण, दुनिया अब 1970 के दशक में आयी तृतीय औद्योगिकी क्रांति के दौर से निकल कर चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रविष्ट कर गयी है। विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि, इस क्रांति का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, उत्पादन सम्बन्ध एवं समाज पर बहुआयामी एवं दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौर में न केवल वर्तमान उत्पादन की पद्धतियां बदलेंगी बल्कि, वैश्विक आर्थिक केंद्र एवं वैश्विक आर्थिक संतुलन भी बदलने वाला है। इस दौर में अर्थ एवं ज्ञानशक्ति का लम्बे समय तक केंद्र बने रहे अमेरिका, यूरोप, जापान, रूस, सिंगापुर कोरिया जैसे विकसित देशों से हटकर नया केंद्र चीन, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम आदि की ओर होने वाला है। चौथी औद्योगिक क्रांति का आधार नॉलेज इंटेंसिव प्रोडक्ट एवं प्रोसेस होगा, जिसके लिए एक ओर जहां ज्ञान उद्योग को विकसित करने हेतु बड़े पैमाने पर भौतिक अधः संरचना एवं मानव संसाधन पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी वहीं, इसको आगे बढ़ाने के लिए युवा एवं नवोन्मेषी दिमाग रखने वाले उच्च शिक्षित एवं प्रशिक्षित स्वस्थ युवकों की आवश्यकता होगी। निःसंदेह आज के समय में भौतिक पूंजी की उपलब्धता में चीन, भारत से तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हो सकता है किन्तु, भारत जनसंख्या के जनांकिकी लाभ के दौर में अनुपातिक रूप से बेहतर युवा जनसँख्या अनुपात होने के कारण चीन से बेहतर स्थिति में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्त्व वाली केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 21वीं सदी की चुनौतियों से निबटने एवं उपजे अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से, नई शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निश्चय एक महत्वपूर्ण कदम है।

आर्थिक विकास के स्तर एवं गति के निर्धारण में तकनीकी एवं नवप्रवर्तन की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। हमारे पूर्वज सदियों पूर्व ज्ञान एवं ज्ञानियों के महत्व को जानते एवं समझते थे। विद्वानों द्वारा ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं उसके सार्वभौमिक महत्व को स्वीकारते हुए भारतीय वांग्मय में उन्हें राजा से भी अधिक महत्व देने की बात कही गयी है जिसका इस उक्ति से पता चलता है 'विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते।।'

भारतीय ज्ञान एवं विज्ञान की परंपरा जहां एक ओर मनुष्य को मोक्ष की राह की ओर जाने के रास्ते को बताती है वहीं उसी ज्ञान के माध्यम से लोक जीवन में सुख एवं समृद्धि के उच्च स्तर को परिश्रम के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग भी सुझाती हैं। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा अद्वितीय इस सन्दर्भ में थी कि यह संकुचित लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित न होकर, किन्वंते विश्वआर्यम, वसुधैवकुटुंबकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे व्यापक एवं श्रेष्ठ लक्ष्यों का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय विद्वान एवं मनीषी समाज में रहते हुए अथवा समाज से दूर रहकर, मानव जीवन में उत्कृष्टता हेतु लोकोपयोगी वस्तुओं, सेवाओं एवं तकनीकी तथा नियम के निर्माण हेतु आवश्यक तकनीकी की खोज एवं संवर्धन हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। ज्ञान को ईश्वर की देन एवं समाज की थाती मानते हुए, वे कॉपीराइट अथवा पेटेंट को आवश्यक नही मानते थे। ज्ञान के केंद्र गुरुकुल एवं आश्रम अपने व्यय हेतु राज्यश्रित न होकर समाज–पोषित थे। शोध के विषय स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने जाते थे ताकि, उसका स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक परीक्षण एवं पुनरीक्षण किया जा सके एवं उसमे आवश्यक सुधार किया जा सके।

ऐसा माना जाता है कि गुरुकुलों से गोत्र परंपरा विकसित हुई। गुरुकुलों में समाजपयोगी विषयक शिक्षा की व्यवस्था थी जिसमें अनेकों तरह के विशेषज्ञ होते थे। गुरुकुल शिक्षा के पूर्ण होने एवं विषय में पारंगत होने का प्रमाणपत्र समाज में प्रदर्शन/प्रतियोगिता के माध्यम से करना होता था तथा समाज द्वारा अनुमोदित होने पर ही उसे विद्वान के रूप में स्वीकृति मिलती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन की प्रकिया न केवल पारदर्शी थी बल्कि, निष्पक्ष भी थी। समाज पोषित होने एवं समाज की निरंतर दृष्टि होने के कारण शिक्षक एवं विद्यार्थियों पर उत्तरोत्तर बेहतर करने का नैतिक एवं सामाजिक दबाव बना रहता था। संस्थाओं के विस्तार एवं सघनता का पता इसी बात से चलता है कि भारत के अनेकों आक्रान्ताओं के निरंतर आक्रमण झेलने के बावजूद भी 17वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रत्येक गांव अथवा गांव संकुल में कम से कम एक गुरुकुल कार्य कर रहा था जिसकी पुष्टि अनेकों अंग्रेजी प्रशासकों एवं विद्वानों ने समय–समय पर की है। ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान एवं आपसी संचार हेतु सेमिनार, कांफ्रेंस, शास्त्रार्थ, प्रवास एवं प्रवचन की नियमित व्यवस्था थी। भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा न केवल प्राचीन है वरन् अद्वितीय है। इसी का परिणाम था कि भारत सहस्त्राब्दियों तक अर्थव्यवस्था एवं ज्ञान का केंद्र एवं विश्व गुरु बना रहा। भारत की इसी ज्ञान परंपरा की समृद्धि से आकृष्ट होकर दुनिया भर के लोग भारत की धरा की ओर आकर्षित हुए एवं यहीं से सीखकर अपने देश जाकर अपना ज्ञान एवं विज्ञान संवर्धित किया। अब तो पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकारने लगे हैं कि यूरोप के आधुनिक ज्ञान की जननी भारत की धरती है। भारत के

ऐतिहासिक संवृद्धि की पुष्टि प्रो. अंगास मेडिसन के नेतृत्त्व में ओइसीडी द्वारा वित्त पोषित शोध से भी होती है। इस अध्ययन के अनुसार प्रथम ईसवी से लेकर छठी सदी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृहत्तर भारत का योगदान एक तिहाई से भी अधिक था जबकि पूरे पश्चिमी यूरोप का हिस्सा 10 प्रतिशत से भी कम था। इतना ही नहीं, प्रथम औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारत का विश्व जीडीपी में हिस्सा पूरे पश्चिमी यूरोप के हिस्से से भी अधिक था (सन्दर्भ हेतु ग्राफ देखें)

ग्राफ : वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न देशों का हिस्सा

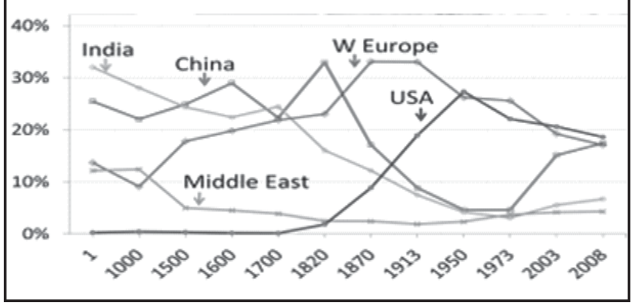

श्रोत : लेखक द्वारा अंगुस मेडिसन की पुस्तक "The World Economy : A Millennial Perspective" से प्राप्त आंकड़ों से तैयार किया गया है।

ज्ञातव्य है कि प्रथम औद्योगिकी क्रांति का दौर सन् 1760 से लेकर 1830 के मध्य माना जाता है जब उत्पादन पद्धति में प्रयोग होने वाले जैविक शक्ति (मानव श्रम एवं पशु की शक्ति) का स्थान जेम्सवाट द्वारा विकसित पानी एवं भाप की शक्ति ने लिया। इस नवीन तकनीकी का प्रयोग करते हुए यूरोप में बड़े स्तर पर उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में मशीनीकरण किया गया। औद्योगिक क्लस्टर विकसित हुए तथा औद्योगीकृत समाज की संरचना विकसित हुई। यह समाज, सदियों से चली आ रही पुरानी परिवार पद्धति तथा स्थानीय आर्थिक लेने–देने की कृषिगत व्यवस्था से अलग था जिसमें समाज के विभिन्न घटकों के अन्तर्सम्बन्ध संकुचित हुए क्योंकि संबंधों का आधार लाभ एवं बाजार था। इसी का परिणाम रहा कि प्रथम औद्योगिक क्रांति के दौर में यूरोप में अतिलाभ, लिप्सा से ओत प्रोत पूंजीवाद के इर्द गिर्द बुने औद्योगिक समाज एवं दुनिया को शताब्दियों तक उपनिवेशवाद एवं शोषण का दंश भी झेलना पड़ा।

आर्थिक विकास के इतिहास में द्वितीय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत उत्पादन असेम्बली में बड़े पैमाने पर बिजली के प्रयोग से मानी जाती है। बिजली के प्रयोग ने न केवल ऊर्जा उत्पन्न करने में होने वाली ऊष्मा की हानि को कम किया बल्कि ग्रिड एनर्जी मिलने से उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा एवं मशीनों के आकार को सीमित कर उत्पादन की गति गुणवता को भी बेहतर किया। चूँकि, यूरोप का उत्पादन का आधार भाप उर्जा आधारित प्रथम औद्योगिक क्रांति था इसलिए द्वितीय औद्योगिक क्रांति का स्वाभाविक लाभ नये उत्पादन क्षेत्रों एवं नये देशों को मिला। इस दौर में उत्पादन की गति तेज होने एवं प्रतियोगिता के कारण कीमतों में गिरावट के कारण बाजार पर कब्जे की होड़ हो गयी एवं अंतिम परिणिति दो विश्वयुद्ध एवं अनेकों छोटे–छोटे युद्धों के साथ मानवता को काफी हानि उठानी पडी। इस दौर में मशीनों को उर्जा कुशल, छोटा एवं ऑटोमेशन करने हेतु तकनीकी को बेहतर करने पर शोध किया गया जिसका स्वाभाविक लाभ अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी एवं उपनिवेशवाद के दौर से निकले आशियान के कई देशों को मिला। उत्पाद असेम्बली लाइन के विकेंद्रीकरण एवं मशीनों के आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन की आकांक्षा में ही कंप्यूटर की खोज हुई जिसमें तृतीय औद्योगिक क्रांति की आधारशिला रखी।

21वीं सदी में तकनीकी नवप्रवर्तन, ज्ञान में निरंतर प्रगति एवं प्रतियोगिता के कारण वैश्विक आर्थिक क्रम में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहा है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि आने वाली सदी ज्ञान की सदी होगी। कठोर पेटेंट कानूनों, उत्पादों के व्यवसायीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों से ज्ञान पर कुछ देशों एवं संस्थाओं का एकाधिकार भारत जैसे जनसंख्या बहुल देशों के लिए विकास के अवसर एवं चुनौतियों दोनों खड़ा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास सदियों पुरानी किंतु बिखरी ज्ञान की थाती का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

(लेखक शम्भूदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजियाबाद में प्राचार्य हैं)

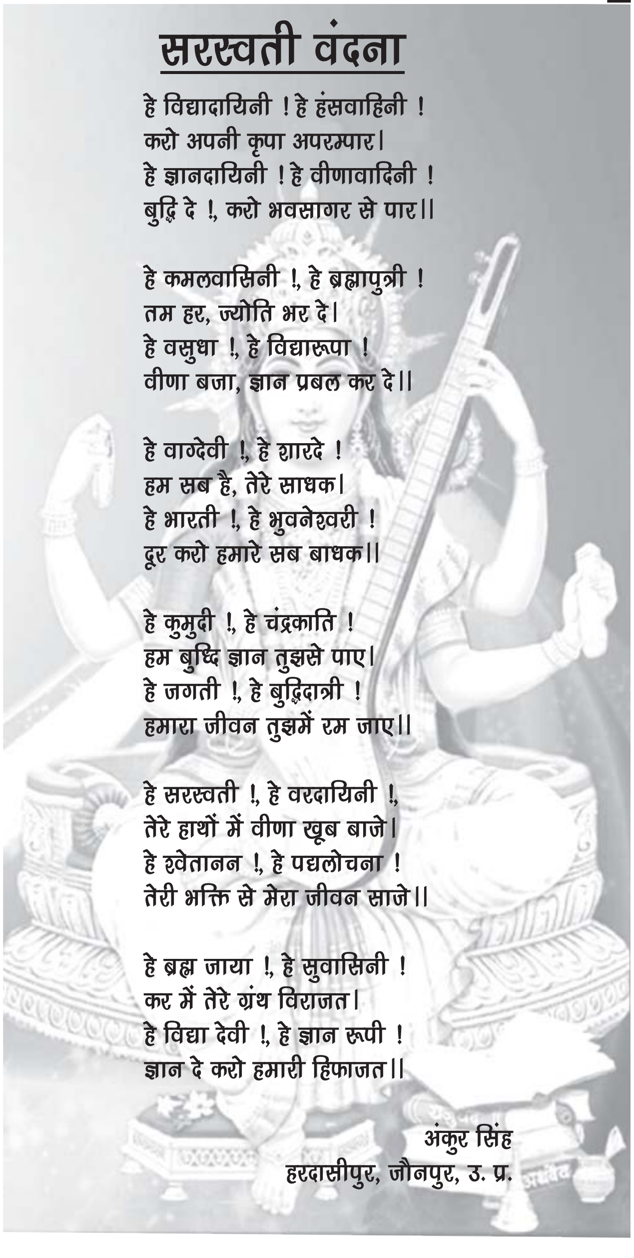

सरस्वती वंदना

हे विद्यादायिनी ! हे हंसवाहिनी !
करो अपनी कृपा अपरम्पार।
हे ज्ञानदायिनी ! हे वीणावादिनी !
बुद्दि दे !, करो भवसागर से पार।।

हे कमलवासिनी !, हे ब्रह्मापुत्री !
तम हर, ज्योति भर दे।
हे वसुधा !, हे विद्यारूपा !
वीणा बजा, ज्ञान प्रबल कर दे।।

हे वाग्देवी !, हे शारदे !
हम सब है, तेरे साधक।
हे भारती !, हे भुवनेश्वरी !
दूर करो हमारे सब बाधक।।

हे कुमुदी !, हे चंद्रकाति !
हम बुध्दि ज्ञान तुझसे पाए।
हे जगती !, हे बुद्दिदात्री !
हमारा जीवन तुझमें रम जाए।।

हे सरस्वती !, हे वरदायिनी !,
तेरे हाथों में वीणा खूब बाजे।
हे श्वेतानन !, हे पद्मलोचना !
तेरी भक्ति से मेरा जीवन साजे।।

हे ब्रह्म जाया !, हे सुवासिनी !
कर में तेरे ग्रंथ विराजत।
हे विद्या देवी !, हे ज्ञान रूपी !
ज्ञान दे करो हमारी हिफाजत।।

अंकुर सिंह
हरदासीपुर, जौनपुर, उ. प्र.

ISSN No. 2581-3528

समृद्ध विरासत की पावन भूमि उत्तर प्रदेश

प्रोफेसर डॉ. हरेन्द्र सिंह

उत्तर प्रदेश की भूमि वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक निषाद द्वारा, क्रीडारत क्रौञ्च पक्षी के मारे जाने की घटना देखकर, करुणा से वशीभूत महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा था और उनके मुख से स्वयं ही यह पद्य फूट पड़ा था –

"मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम।।"

उपरोक्तानुसार महर्षि वाल्मीकि की वाणी अनुष्टुप छंद में फूटी थी जो कि लौकिक संस्कृत भाषा का श्लोक था। उसी वाणी में उन्होंने आदर्श पुरुष भगवान श्री राम की कथा लिखी।

उत्तर प्रदेश एक बहुत ही विशेष समृद्ध विरासत वाला राज्य है। इस राज्य को इन्द्रधनुष की जमीन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, यहां की समृद्ध संस्कृति बहुत ही आकर्षक और लुभावनी है। उत्तर प्रदेश ने अपने पारंपरिक रीति–रिवाजों और प्रथाओं का पालन करते हुये प्राकृतिक उपहारों के अलावा सांस्कृतिक तत्वों की समृद्ध विरासत का पोषण किया है। उत्तर प्रदेश को भारतीय इतिहास में दो महान महाकाव्यों महाभारत और रामायण को सर्वश्रेष्ठ करने का गौरव प्राप्त है। महाभारत की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग हस्तिनापुर के आस–पास मानी जाती है जबकि रामायण की पृष्ठभूमि में इस राज्य का पूर्वोत्तर भाग आता है। उत्तर प्रदेश के पौराणिक स्रोतों के अंतर्गत मथुरा एवं वृन्दावन के आस–पास का क्षेत्र है जोकि भगवान श्री कृष्ण से संबन्धित है।

उत्तर प्रदेश की पवित्रता और महानता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि इस राज्य की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम की अयोध्या इसी प्रदेश में है। हिन्दू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा शहर में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण की यह मथुरा नगरी भी इसी राज्य में है। इस राज्य की पृष्ठभूमि बहुत ही पुरानी है। लम्बे समय से यहां पर कई तरह के लोग आये और चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी संस्कृति, वास्तुकला इस राज्य को विरासत में दे दी। इसीलिए यहां पर कई तरह के मंदिर, ऐतिहासिक स्मारक, प्राचीन विहार नजर आते हैं।

जब आर्यों का आगमन हुआ तो वे इसे "मध्यदेश" या मध्य देश कहते थे, इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारम्भ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिन्धु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दो–आब अर्थात् यमुना और गंगा का मैदानी भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त्त या भारतवर्ष (भरत आर्यों के एक प्रमुख राजा थे) पड़ा। समय के साथ–साथ आर्य भारत के दूरस्थ भागों में फैल गये। आर्यों के निवास के दिनों के दौरान ही इस क्षेत्र में महाभारत, रामायण, ब्राह्मण और पुराणों के महाकाव्यों की रचना की गई थी। संसार के प्राचीनतम नगरों

ISSN No. 2581-3528

में से एक माना जाने वाला वाराणसी नगर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखण्डी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे–छोटे राज्यों में बंट गया या फिर बड़े साम्राज्यों, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज गुर्जर–प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केन्द्र था।

उत्तर प्रदेश की संस्कृति भारतीय पारंपरिक रीति–रिवाजों और प्रथाओं की एक पालना है। इसमें न केवल हरे–भरे परिदृश्यों, नदियों का ढेर है, बल्कि सांस्कृतिक तत्वों की समृद्ध विरासत का भी पोषण किया गया है। ऋग्वेद की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश की इस मिट्टी में हुई थी। पूरे राष्ट्र में भारतीय महाभारत और रामायण भी राज्य द्वारा प्रदत्त सबसे उत्तम उपहार हैं। संगीत, त्यौहार, स्वादिष्ट भोजन और उत्तम दर्जे की जीवन शैली उत्तर प्रदेश की संस्कृति को प्रथागत, फिर भी, देवभूमि के रूप में दर्शाती है।

यूं तो उत्तर प्रदेश की प्राचीनता पाँच हजार वर्ष से भी अधिक है परन्तु सन् 1950 में इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। भारत वर्ष की स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व उत्तर प्रदेश को युनाइटेड प्रॉविंस के नाम से जाना जाता था। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेजिडेन्सी के अन्तर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रान्त (आरम्भ में आगरा प्रेजिडेन्सी कहलाता था) गठित किया गया। 1856 ई. में कम्पनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप) के नाम से इसे 1877 ई. में पश्चिमोत्तर प्रान्त में मिला लिया गया। 1902 ई. में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रान्त कर दिया गया।

सन 1902में नार्थ वेस्ट प्रॉविन्स का नाम बदल कर यूनाइटेड प्रोविन्स ऑफ आगरा एण्ड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन् 1920में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गयी। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी सन् 1950 को इस संयुक्त प्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। उत्तर प्रदेश का अधिकतम हिस्सा अवध राज्य के अधीन था। अवध यानि आज का मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा। इस हिस्से में लखनऊ से फैजाबाद तक का भूभाग आता था।

उत्तर प्रदेश मे तीन विश्व धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी है। धार्मिक विरासत के क्षेत्र मे उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि राज्य में कई हिन्दू मन्दिर हैं। हिन्दू धर्म की पवित्रतम सप्त पुरियों के सात नगरों में से तीन अयोध्या, मथुरा व वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। वाराणसी हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। वृंदावन को वैष्णव सम्प्रदाय का भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध अयोध्या महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। विन्ध्याचल एक अन्य हिंदू तीर्थ स्थल है जहाँ विंध्यवासिनी देवी का मन्दिर स्थित है। उत्तर प्रदेश मे कई बौद्ध स्तूप और मठ शामिल हैं। सारनाथ में स्थित अशोकस्तम्भ और अशोक का सिंहचतुर्मुख स्तम्भशीर्ष राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण पुरातात्विक कलाकृतियाँ हैं।

वैदिक साहित्य मन्त्र, ब्राह्मण, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रौं, आदि महाकाव्य–वाल्मीकि रामायण, और महाभारत, जिसमें श्रीमद् भगवद्गीता शामिल है, अष्टादश पुराणों के उल्लेखनीय हिस्सों का मूल यहां के कई आश्रमों में जीवन्त है। उत्तर प्रदेश ने बौद्ध–हिन्दू काल (लगभग 600 ई. पू.–1200 ई.) के ग्रन्थों व वास्तुशिल्प ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत में बड़ा योगदान दिया है। 1947 के बाद से भारत सरकार का चिह्न मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए चार सिंह युक्त स्तम्भ (वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित) पर आधारित है। वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्यकला और हिन्दी व उर्दू भाषाएं यहीं पर फली–फूली है। संगीत परम्परा का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ। तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ यहीं के थे। भारतीय संगीत के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य सितार और तबले का विकास भी इसी प्रदेश में हुआ।

राम के शासन से लेकर अंग्रेजों के शासन तक उत्तर प्रदेश ने सब कुछ देखा है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, स्मारक, साहित्य और विभिन्न कलाएं हमारी विरासत का हिस्सा हैं। इन्हें दुनियाभर में सराहा गया है। हमें ऐसी जीवंत संस्कृति वाले उत्तर प्रदेश पर गर्व है।

(लेखक, सरकार द्वारा 'शिक्षक श्री' विभूषित ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, शैक्षिक प्रशासक, प्रोफेसर एवं चिन्तक हैं)

ISSN No. 2581-3528

आपदा काल में यूपी सरकार का कुशल प्रबन्धन

अनुपमा अग्रवाल

मार्च 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी (कोविड–19) की भयावहता को भांपते हुए देश में लॉकडाउन का अहम फैसला लिया, जिससे देश में संक्रमण की दर तो नियंत्रित हुई ही साथ ही मौत का आंकड़ा भी वैश्विक आंकड़ो की अपेक्षा बहुत कम रहा। विगत दो वर्षों की कोरोना की समयावधि में जब दुनिया के विकसित और महाशक्ति बनने की होड़ में शामिल देश, कोरोना के आगे विवश और लाचार नजर आ रहे थे, उस समय भारत आधुनिक चिकित्सा संसाधनों की कमी के बावजूद केवल सरकारी प्रयासों, आपसी सहयोग, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं कुशल प्रबन्धन के बलबूते कोरोना के प्रसार को रोक पाने में सफल रहा। इसके पश्चात भारत ने कम समय में अपनी स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर सर्वाधिक टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया व अन्य देशों को निःशुल्क वैक्सीन, दवा एवं चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराकर विश्व का नेतृत्व किया तथा कोरोना काल में भारत की प्राचीनतम चिकित्सा विधाओं योग व आयुर्वेद के सफल नतीजों ने, आत्मनिर्भर बनने के अतिरिक्त विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद आज भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ पूरी ताकत व दृढ़ता से कोरोना की तीसरी लहर से निपट रहा है।

चीनी वाइरस कोविड–19 ने जब देश में पहली बार दस्तक दी उस समय तक आमजन उसके घातक प्रभाव से पूरी तरह अनजान थे तथा जब तक राज्य सरकारें कुछ प्रभावी कदम उठाती तब तक मरीजों की संख्या में गुणात्मक रूप से वृद्धि होने लगी और उत्तर प्रदेश के जिलों व अन्य महानगरों में स्थिति बिगड़ने लगी। इस गम्भीर होती स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस जिम्मेदारी, सजगता एवं समझदारी का परिचय दिया वह सराहनीय है। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत कुशलता से कोरोनाजन्य परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा की।कोरोना काल में प्रदेश में न्यायालय के आदेश पर पंचायत चुनावों के बावजूद कोविड को नियंत्रित करने तथा लॉकडाउन के समय अंतिम व्यक्ति तक घर पर ही सरकारी सहायता पहुंचाने का जो सफलतापूर्वक कार्य योगी सरकार द्वारा किया गया उसी की बदौलत आज जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य होने के बाद भी अन्य राज्यों की तुलना में यहां जनहानि काफी कम हुई।योगी जी के इस कुशल प्रबन्धन को न् केवल देश के प्रधानमंत्री ने सराहा बल्कि विपक्ष समेत दुनिया के कई देशों ने इसकी तारीफ की और तो और ऑस्ट्रेलिया सरकार में मंत्री जेसन वुड ने अपने ट्वीट के माध्यम से योगी जी की प्रशंसा करते हुए यूपी सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी व्यक्त की। लॉक डाउन के दौरान लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का काम हो या घर घर राशन पहुंचाना या फिर आमजन तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना,सभी कार्यों के कुशल प्रबन्धन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यूपी में न् सिर्फ अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है बल्कि कोविड कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम प्रत्येक जिले में स्थापित कर कोरोना रोकने के लिए बेहतर प्रबन्धन किया है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना की पहली लहर से जब हालात तेजी से बिगड़ने लगे तो उसे नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने टीम–11 का गठन किया जिसे बाद में टीम –9 का नाम दिया गया। इस टीम के कुशल संचालन हेतु कुछ निर्देश जारी किए गए तथा उचित परिणामों की जानकारी हेतु स्वयं योगी जी द्वारा प्रतिदिन निश्चित समय पर इस टीम के कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। टीम ने 'ट्रेस, टेस्ट व ट्रीट' की रणनीति तैयार करने के साथ ही प्रदेशवासियों को टीकाकरण का सुरक्षा कवच प्रदान करने की रणनीति भी बनाई। बाद में जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और तभी से प्रतिदिन नए मामलों में कमी व स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। संबंधित प्रभारी मंत्री अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधि को किसी न् किसी टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया गया ताकि लोगों का उत्साहवर्धन हो सके तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री के स्तर से वैक्सीन निर्माता कंपनी से सतत् सम्पर्क बनाये रखने का निर्देश जारी किया गया। साथ ही संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गांव गांव टेस्टिंग का महा अभियान चलाया गया, जिसमें आमजन ने भी पूर्ण सहयोग किया। निगरानी समिति ने घर घर जाकर लोगों की जांच की और होम आइसोलेशन के मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने के अतिरिक्त लक्षण युक्त लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया। जिले के जिलाधिकारी एवं चिकित्साधिकारी ने सुनिश्चित किया कि जांच की प्रक्रिया गांवों में ही हो ताकि समय से रिपोर्ट के आधार पर इलाज आरम्भ किया जा सके।

होम आइसोलेशन में उपचाराधीन लोगों को समय से मेडिकल किट उपलब्ध कराना व उनका पूर्ण विवरण स्थानीय स्वास्थ विभाग को उपलब्ध कराना तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से इसका पुनः सत्यापन किया गया। साथ ही होम आइसोलेशन के मरीजों से प्रतिदिन संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाने व टेली कंसल्टेशन के

ISSN No. 2581-3528

माध्यम से मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस परिवहन को स्थगित कर निजी परिवहन आधी क्षमता के साथ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित करने का निर्देश जारी किया गया।इसके अतिरिक्त मरीजों को जरूरत के अनुसार तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों में पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री योगी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर जनता से संवाद स्थापित करने तथा घर से निकलते वक्त मास्क और सेनेटाइजर के इस्तेमाल का जनता को निर्देश जारी किया तथा बढ़ते मामलों को कम करने के लिए भीड़–भाड़ वाली जगहों की बजाए खुले में जरूरी सामग्री बेचने की व्यवस्था की गई।योगी जी ने पूरे प्रदेश में स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण कर, कार्य कर रहे अधिकारियों का हौसला बढ़ाया तो वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्ती भी बरती। योगी जी ने कोरोना की पहली लहर में पैदल अपने घरों को लौटते प्रवासी मजदूरों को गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए रातों रात 1,000 बसें लगाई साथ ही उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था की।

प्रदेश सरकार ने श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों के भरण पोषण हेतु खाते में एक हजार रुपये की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी तथा निर्देश जारी किया गया कि कोई भी मकान मालिक किसी भी कामगार अथवा मजदूर से एक महीने का किराया वसूल नहीं करेगा।जबकि सरकारी और गैरसरकारी कार्यालयों को खुलवा कर कर्मचारियों को एक माह का वेतन देने का निर्देश दिया गया।खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 24.73 परिवारों को लगभग 1.17 करोड़, गरीब व मजदूरों को 78947 मीट्रिक टन अनाज वितरण किया गया जो अगले तीन महीने तक जारी रहा। टीम 9 के इस कुशल प्रबंधन से न् केवल कोरोना की रोकथाम में मदद मिली बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्रबंधन की बागडोर अपने हाथ में रखकर प्रतिदिन समीक्षा लेने वाले योगी जी की कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण इस बात में दिखता है कि जब गतवर्ष टीम के साथ बैठक के दौरान उन्हें अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला, जिसे सुनकर उनकी आंखें नम हो गई परन्तु उन्होंने पिताजी की अंत्येष्टि में सम्मिलित होने की बजाय प्रदेश की जनता की सेवा व दायित्व के निर्वहन को महत्ता दी।

कोविड–19 से निपटने व आपदा को अवसर में बदलने का जो महत्वपूर्ण कार्य यूपी की योगी सरकार ने किया वह अन्य देशों व राज्यों के लिए किसी सीख से कम नहीं है। कुशल प्रबंधन के अंतर्गत टेस्ट की मात्रा बढ़ाकर, संक्रमण दर को पांच फीसदी से नीचे रखकर,मृत्यु दर को एक फीसदी से कम करके, वैक्सीन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा कर व कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेक्सीन लगाने का सफलता पूर्वक काम किया। इसी के साथ योगी जी ने चीन से मोहभंग हुए विदेशी व्यापारियों के लिए यूपी के द्वार खोल दिए तथा 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना को प्रोत्साहित कर देसी वस्तुओं को विदेशी बाजार में पहचान दिलाने हेतु बैंकों से कम कीमत पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जिससे कोरोना की समयावधि में यूपी की अर्थव्यवस्था कमजोर होने की बजाय और अधिक मजबूत हुई।

(लेखिका, समाज सेविका एवं पत्र लेखिका हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

यूपी के रण में कानून व्यवस्था पर जनता का रिपोर्ट कार्ड

अनीता चौधरी

इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व सरकारों की तुष्टिकरण की राजनीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश की गिनती और पहचान एक असुरक्षित और बीमारू राज्य के रूप में होती रही। यह छवि आधारहीन नहीं थी, बल्कि इसके अनेक कारण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था और असंख्य अपराधी यहां सक्रिय थे। निरंकुश अपराध के कारण निश्चित ही आम आदमी, खासकर व्यापारियों और महिलाओं में निरंतर भय और असुरक्षा व्याप्त थी। तुष्टिकरण की राजनीति ने एक विशेष समुदाय के अपराधियों को बेलगाम कर रखा था। इनके अपराधों के कारण लोग यहां से पलायन करने लगे। कैराना क्षेत्र इसका सर्वाधिक उपयुक्त उदहारण है। इस छवि की वजह से अन्य हानियों के अलावा मुख्य नुकसान यह हुआ कि पूर्व में यूपी में कोई विशेष निवेश नहीं हुआ, उद्योग–धंधे वांछित रूप से पनप नहीं पाए और विकास की दौड़ में यह राज्य अपेक्षाकृत पिछड़ेपन का शिकार रहा।

यूपी में विधानसभा चुनाव है और सरकार के कार्यों को लेकर जनता की रिपोर्ट कार्ड तैयार है। वैसे तो औद्योगीकरण, निवेश, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, सेहत, यह वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में अहम होते हैं। सरकार इन्हीं मुद्दों पर अपने कार्यों का लेखा लेकर पाँच साल बाद जनता के बीच जाती है। यह मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार के अपने आंकड़े होते हैं जिसमें आँकड़ों को ऊपर नीचे करना सम्भवतः सरकार के हाथों में होता है। इन कार्यों के आधार पर सरकार की छवि बनती है और लोग अगर संतुष्ट नहीं हों तो कुछ हद तक बिगड़ भी सकती हैं। मगर कानून–व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी प्रदेश की जनता की उसकी खुद की अनुभूति होती है, जिसका रिपोर्ट कार्ड अपने अनुभव के आधार पर सिर्फ जनता तैयार करती है। अपराध और माफियागिरी पर लगाम, बेटियों की सुरक्षा, अराजकता का खात्मा, ये सभी वो मुद्दे हैं जिनसे जनता का सीधा सरोकार होता है। इसीलिए प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चिंता होती है। खासकर तब ये चिंता और बढ़ जाती है जब कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर कोई सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता का इतिहास रची हो। जी हाँ हम इस लेख में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के अहम मुद्दे पर योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर इस लेख में उसी उत्तर प्रदेश पर बिंदुवार बातें करेंगे जो पाँच साल पहले मफियाओं और अपराधियों का गढ़ माना जाता था। एक ऐसा बीमारू राज्य जिसे कानून व्यवस्था के लिहाज से उल्टा प्रदेश भी कहा जाता था। बाकि सारी उपलब्धियों को वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आंकड़ों के आधार पर जनता के सामने खुद रख रही है लेकिन जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की बात आती है तो इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सरकार से ज्यादा जनता अपने अनुभवों को रख रही है। इस मुद्दे पर जनता के पास अखिलेश यादव और मायावती की सरकारों से योगी सरकार की तुलनात्मक रिपोर्ट है। बतौर पत्रकार मैं जब उत्तर प्रदेश के रण में जनता का दिल टटोलने पहुंची तो चुनाव का जो मूड समझ में आ रहा था उसे देखते हुए यही लगा कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भी कहीं न कहीं मुद्दा कानून व्यवस्था के आस–पास ही घूमने वाला है। कानून व्यवस्था और अपराधियों पर योगी सरकार की नकेल को नोएडा से लेकर गाजियाबाद, बनारस से लेकर प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर हर जगह चर्चा में सभी बातों में एक बात जो सामान्य थी वो यह कि, 'बड़ा सुकून ह भइया गुंडन को तो एकदम हौंक दिहिन हैं महाराज जी' (महाराज जी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ)। लोगों के मूड को देख कर ऐसा लगा कि कानून व्यवस्था को लेकर जनता के रिपोर्ट कार्ड में योगी सरकार डिस्टिंक्शन के साथ पास होने वाली है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इन पांच वर्षों में निःसंदेह अनेक क्षेत्रों में असंख्य उत्कृष्ट कार्य किए हैं। परंतु उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने एवं कानून का राज स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा और जनता के साथ समर्पण भाव से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए जो नागरिकों को अपनी सुरक्षा और जनकल्याण की दृष्टि से बेहद उपयोगी लगे।

2017 में जब प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में कमल खिला तो भगवाधारी, मठ निवासी योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के साथ ही कीचड़ का सफाया तीव्र गति के साथ होना शुरू हुआ। आइए योगी सरकार की अपराध नियंत्रण की नीति और किए गए कार्यों पर पूरी नजर डालते हैं।

अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति :– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति जीरो टोलरेंस नीति अपनाते हुए अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान छेड़ दिया। अपराध रोकने के लिए योगी सरकार ने असंख्य कदम उठाए व अनेक योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया। उन्होंने कहा कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर। जिसका परिणाम यह हुआ कि यूपी पुलिस माफिया और कुख्यात अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़ी।

माफियागिरी पर योगी का बुलडोजर – पुलिस ने सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नहीं, बल्कि प्रदेश के ऐसे 25 बड़े माफिया को चिह्नित किया, जिनके नाम से लोगों में दहशत हो जाती थी और उनका 'सिक्का' हर सरकार में चलता था। माफिया और कुख्यात अपराधियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने लगा। अपराधियों का साम्राज्य रेत के टीले की तरह ध्वस्त होने लगा। आज बड़े–बड़े माफिया और अपराधी यूपी आने से या तो डरते हैं या फिर जेल में हैं।

सिर्फ कार्यवाही नहीं, सजा भी जरूरी :– मुख्यमंत्री योगी के दिशा निदेश में यूपी पुलिस चिह्नित माफिया के खिलाफ दर्ज मुकदमो में तेजी से कार्यवाही करती रही, ताकि उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। चिह्नित सभी बड़े माफिया इस समय जेल में बंद हैं। अदालती करवाई में कुछ की सजा भी तय हो चुकी है।

ये हैं वो कुख्यात 25 माफिया जिनपर योगी सरकार की हंटर और बुलडोजर चली :– गाजीपुर जिले के युसूफपुर मोहम्दाबाद निवासी मुख्तार अंसारी, प्रयागराज जिले के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र निवासी अतीक अहमद, वाराणसी जिले के चौबेपुर निवासी बृजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, लखनऊ जिले के हसनगंज निवासी ओमप्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र निवासी मुनीर, अंबेडकरनगर जिले के हंसवार थाना क्षेत्र निवासी खान मुबारक, गाजियाबाद जिले के लोनी निवासी अमित कसाना, शामली जिले के आदर्श मंडी निवासी आकाश जाट, मेरठ जिले के सरूरपुर निवासी उधम सिंह, मेरठ जिले के सरूरपुर निवासी योगेश भदौड़ा, बागपत जिले के बड़ौत निवासी अजीत उर्फ हप्पू, मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुर निवासी सुशील उर्फ मूंछ, मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली निवासी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, गौतमबुद्धनगर जिले के कासना निवासी सुन्दर भाटी उर्फ नेताजी, गौतमबुद्धनगर जिले के कासना निवासी अनिल भाटी, गौतमबुद्धनगर जिले के बादलपुर निवासी अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर, गौतमबुद्धनगर जिले के दनकौर निवासी सिंघराज भाटी, गौतमबुद्धनगर जिले के जारचा निवासी अंकित गुर्जर, वाराणसी जिले के कोतवाली निवासी सुभाष सिंह ठाकुर, आजमगढ़ जिले के जीयनपुर निवासी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद उमेश राय उर्फ गौरा राय, गाजीपुर जिले के सैदपुर निवासी त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. सलीम, लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. सोहराब और लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. रुस्तम हैं।'

एनकाउंटर में 139 से ज्यादा अपराधी ढेर, 13 जवान भी शहीद :– सीएम योगी के कार्यकाल में 15 दिसंबर 2021 तक लगभग 139 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 3427 घायल हुए। इन कार्यवाहियों में पुलिस बल के 13 जवान भी शहीद हुए और 1155 पुलिस कर्मी घायल हुए। जिनकी बहादुरी के लिए सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। 25 हजार के ईनामी 9157 अपराधी, 25 से 50 हजार के ईनामी 773 अपराधी और 50 हजार से अधिक के 91 ईनामी अपराधी यानि कुल 10,021 जेल भेजे गए। गैंगस्टर एक्ट में 44759 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 630 अभियुक्त रासुका में किये गए।

इन पर भी कसा शिकंजा :– माफिया के खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही में अवैध बूचड़खाना और स्लाटर हाउस के ध्वस्तीकरण, पार्किंग ठेके की आड़ में अवैध वसूली पर लगाम, अवैध मछली कारोबार, सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने के सघन प्रयास, अपराधी शूटरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, ठेकेदार माफिया के खिलाफ कार्यवाही, कोयला कारोबार से अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति के जब्तीकरण आदि की कार्यवाहियां प्रमुख हैं।

उत्तम प्रशासन, निवेश और रोजगार बढ़ाने के वादे पर भाजपा 2017 में यूपी में अपना परचम लहराई थी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अथक प्रयास भी किए। लेकिन सरकार की सभी योजनाओं को महिलाओं को ध्यान में रख कर लागू किया गया। इन सभी में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध सर्वप्रथम रहे। 25 माफिया की नौ अरब की चल और अचल संपत्ति पर भी सीएम योगी का बुलडोजर चला।

महिलाओं के उत्थान के लिए 2017 के बाद जमकर काम हुए :– इन पांच साल के दौरान प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए जमकर काम किया। उज्ज्वला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, शबरी संकल्प अभियान, महिला शक्ति केन्द्र, किशोरी बालिका योजना, मुख्यमंत्री सश्रम सुपोषण योजना, सखी सेंटर, महिला हेल्पलाइन 1090, मिशन शक्ति, घरौनी योजना, मातृ वंदना योजना, कन्या सुमंगला योजना, एंटी रोमियो स्क्वॉड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एवं स्वामित्व योजना के तहत सीधे तौर पर महिलाओं को योगी सरकार में खूब लाभ मिला है। इसके अलावा योगी सरकार ने महिला अपराध रोकने के लिए रात्रि सुरक्षा कवच योजना, महिला सहायता डेस्क, गुलाबी बूथ समेत गुलाबी बस सेवा भी आरंभ की। इन सभी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम राज्य स्पष्ट दिख रहा है।

इसके अलावा अगर देखें तो कानून व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये इन क्षेत्रों। में भी खूब काम हुए :—

- **पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 1.43 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती।**
- **विभिन्न प्रकार के 214 नए थानों की स्थापना।**
- **उत्तरप्रदेश के सभी 1,535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना।**
- **केंद्र की तर्ज पर किया गया यूपी सीआईएसएफ का गठन।**
- **लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का गठन।**
- **एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर आरोपियों पर कार्रवाई।**
- **उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना।**
- **उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर सेल की स्थापना।**
- **सभी जनपदों के एसपी कार्यालयों में खुले एफआईआर काउंटर।**
- **18 जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील की स्थापना।**
- **माफिया, उनके परिजनों और सहयोगियों के 150 से ज्यादा शस्त्र लाईसेंस निरस्त किए गए।**

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों का भी पुराना इतिहास रहा है और पूर्व में समय समय पर राज्य दंगों की आग में झुलसता भी रहा। जिससे जान—माल की असीमित हानि होती थी। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में दंगा मुक्त प्रदेश बनाने में प्रबल इच्छा शक्ति दिखाई और पिछले पांच वर्षो में यूपी को दंगामुक्त रखने का रिकॉर्ड स्थापित किया। कोई भी दंगा नहीं होना निश्चित ही योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपराध तेजी से घटे हैं। दुष्कर्म के मामलों में उत्तर प्रदेश में 45 प्रतिशत की कमी आई जो वर्ष 2016 में 3419 से घट कर वर्ष 2020—21 में 2317 रह गए।

पुलिस और आम नागरिकों से हुई बातचीत के आधार पर ये बात सामने आयी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के मसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होने से पुलिस को स्वतंत्र होकर काम करने का अवसर मिला। पुलिस की हनक अपराधियों के बीच भय का रूप लेने लगी जो काफी हद तक कारगर सिद्ध हुई। योगी प्रशासन की सख्त नीतियों के चलते आम आदमी के प्रति भी पुलिस का व्यवहार बदला जिसके कारण आम आदमी में सुरक्षा की भावना और पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निश्चित ही अभूतपूर्व दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति, दृढ़निश्चय होकर काम करते हुए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है और पाँच सालों में कानून व्यवस्था को लेकर जनता की रिपोर्ट कार्ड में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

महिलाओं को सशक्त बनाता मिशन शक्ति अभियान

डॉ. नीलम कुमारी

उत्तर प्रदेश में जब हाथरस और बलरामपुर में घटित घटनाओं के कारण राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किये जाने लगे, तब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 17 अक्तूबर 2020 को महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए एक योजना प्रारंभ की जिसे मिशन शक्ति अभियान का नाम दिया गया। इस अभियान के माध्यम से सरकार की इच्छा प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त, स्वाबलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा करने वाले लोगों की पहचान उजागर करना और महिलाओं को राज्य में सुरक्षित महसूस कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में यह अभियान, सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में महिलाओं व बालिकाओं के लिए विशेष प्रयास और नियम कानून तैयार किये गए हैं।

इस योजना ने महिला स्वयं सहायता समूह एवं सखी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखाई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजना ने बालिकाओं और उनके अभिभावकों को बड़ा संबल दिया है।

इस योजना के पहले चरण का शुभारम्भ करते समय इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया था—मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन शक्ति। मिशन शक्ति अभियान का केंद्र बिंन्दु महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने पर था तथा ऑपरेशन शक्ति का केंद्र बिंदु उन लोगों को सजा दिलाने पर था जिन्होंने महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार या अपराध किया है।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब वर्ष 2020 में यूपी मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया था तो अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं दूसरे चरण में अभियान को ऑपरेशन के रूप में संचालित किया किया। मिशन शक्ति के अंतर्गत अब तक 1, 21,509 महिलाओं को मदद मिली है। अब "मिशन शक्ति अभियान के दौरान आपातकालीन सेवा 112 यूपी" एक मिशन की तरह महिलाओं में शक्ति का अहसास बढ़ा रहा है। खासतौर से वीमेन पॉवर लाइन "1090 व 181 सेवा के 112 यूपी से एकीकरण" के बाद महिलाओं को एक ही छत के नीचे सुरक्षा, सम्मान और स्वांवलंबन से जुड़ी सेवाएं एक साथ मिल रही हैं। अब महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना हो या उन्हें परेशान करने वाले शोहदों को सबक सिखाना हो या मुआवजा या सरकारी योजनाओं की जानकारी देना सब एक ही नंबर 112 पर उपलब्ध है।

इस प्रकार से मिशन शक्ति के दो चरण पूरे कर लिए तब प्रदेश में मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण की सफलता के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबधित विभाग और अधिकारियों को मिशन शक्ति अभियान को नवीन ऊर्जा के साथ नई दिशा देने के निर्देश दिए।

21 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन से योगी सरकार ने यूपी में मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया। मिशन शक्ति 3.0 के तहत

मुख्यमंत्री योगी जी ने निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत 29.68 लाख महिलाओं के खातों में 451 करोड़ रुपये व 1.55 लाख बेटियों के खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा महिलाओं के लिए 30.12 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई। इसके अलावा 59 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्ष की शुरुआत की गई। साथ ही 84.79 करोड रुपए की लागत से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण भी कराये जाने की योजना है। महिलाओं में रोजगार को बढ़ने के लिए महिला बटालियन के लिए 2982 पदों पर विशेष भर्ती भी की जाएगी।

मिशन शक्ति के तीसरे चरण में इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा गया। जिले स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनमें स्कूल, कॉलेज के अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को भी जोड़ा गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास पंचायती राज, गृह, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों से परस्पर समन्वय से योजना को सफल बनाने के लिए अधिकारी लगाये गये। सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने महिलाओं और बेटियों से जुड़े आपराधिक घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये।

.महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 75 जिलों की 75000 महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। यह प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकेगा। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत औद्योगिक विकास विभाग द्वारा महिला उद्यमियों में महिला रोल माडल का चयन कर उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को उद्योग केंद्रित मेगा इवेंट का आयोजन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें राजस्व विभाग 8 मार्च तक महिला शिकायतों के निस्तारण के संबंध में सर्वोत्तम कार्य करने वाले पांच तहसीलों के उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को पुरस्कृत करने की योजना भी इसमें बनायी गयी है। वरासत अभियान के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में महिला खातेदारों के वरासत अंकित करने वाले लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों को पुरस्कृत भी इसके अंतर्गत किया जाएगा।

महिला कल्याण व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ऐसी महिलाओं का चयन करना, जिन्होंने समाज में बच्चों व महिलाओं के विकास व सुरक्षा व संरक्षण के लिए असाधारण काम किया है, भी इसमें सम्मिलित है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 8 मार्च को 133639 विद्यालयों में चौपाल लगाने से लेकर एमएसएमई विभाग औद्योगिक यूनिट में महिला सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन के लिए आंतरिक परिवार समिति गठित करने के कार्य, सभी यूनिट महिला डेस्क बनाने व चिकित्सा शिक्षा विभाग महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के कार्य भी इस अभियान में रखे गये हैं।

औद्योगिक विकास विभाग कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान व गाइडलाइंस लागू करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने, सूचना विभाग द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों में 15–15, जिला मुख्यालय पर 10–10, तहसील स्तर पर 5–5 व ब्लाक स्तर पर 2–2 यानी 4292 होर्डिंग लगवाने का कार्य भी इसमें है। परिवहन विभाग महिलाओं को लाइसेंस जारी करने के लिए सभी परिवहन कार्यालयों में कैंप लगा कर अलग से स्लाट आवंटित कर महिलाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाएगा।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत टीमों का भी गठन किया गया है जो कि प्रत्येक ग्राम सभा के अलग–अलग ब्लॉक में जाकर महिलाओं को जागरुक करने का कार्य संपन्न कर रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वावलंबन कैंप भी संचालित किए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं में डेस्टिट्यूट वूमेन पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि योजनाएं शामिल हैं।

मिशन शक्ति अभियान अपने स्लोगन "नारी शक्ति का करो सम्मान, होगा तब ही देश उद्धार" के अनुरूप प्रदेश में प्रगति के पथ पर है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के जो भी केस कोर्ट में जायेंगें उन्हें फास्ट ट्रैक के तहत जल्द से जल्द उसकी सुनवाई की जा रही है, बलात्कार के केस को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी कठोर सजा दिलाना इस अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।

इस अभियान के क्रियान्वयन पर योगी सरकार ने यह भी कहा है कि बलात्कारियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जायेगा, न ही उनके प्रति कोई नरमी बरती जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया है कि अब से उत्तर प्रदेश पुलिस में 20 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही है, इसमें बेटियों की भर्तियां कर राज्य में सभी बेटियों को इसके लिए उत्साहित किया जायेगा। मिशन शक्ति अभियान से राज्य एवं देश के अलग–अलग कई विभागों को भी जोड़ा जायेगा जिसमें अभी 24 विभाग चुने गए है, जो सरकारी या स्थानीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संघटन होंगें।

मिशन शक्ति की विशेषताओं में यह भी सम्मिलित है कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराधी होगा, उसका अपराध साबित हो जाने के बाद उसकी तस्वीर को जगह–जगह चौराहे पर लगाया जाता है, ताकि सभी को पता चले कि अपराधी कौन है और बाकि लोग भी इससे सबक लेकर ऐसा काम करने की सोचे भी न। मिशन शक्ति योजना में जगह जगह पुलिस मनचले और शोहदों की धरपकड़ कर उन्हें कड़ी सजा देगी। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस थानों में महिलाओं के लिए एक अलग कमरे में हेल्पडेस्क होगी जहाँ महिलाओं से पूछताछ के लिए अधिकारी और सिपाही भी महिला होगी। राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम पंचायतों को अभियान के क्रियान्वन को लेकर आदेश दे दिए है।

उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान को काफी सफलता प्राप्त हो रही है। मिशन शक्ति शुरू होने के बाद यूपी में इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। महिलाओं में अपने अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता आ रही है और महिला अपराधों पर भी लगाम लगी है। योगी सरकार का मिशन शक्ति एक सफल मिशन है। योगी सरकार द्वारा चलाई गयी मिशन शक्ति योजना ने महिलाओं पर संजीवनी जैसा असर किया है। इस योजना का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश राज्य की पीड़ित महिलाएं, अपनी शिकायतों को भरोसे के साथ दर्ज कराने, गांवों से निकलकर थानों तक पहुंच रही हैं।

(लेखिका किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलज, सिम्भावली, हापुड में अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं)

ISSN No. 2581-3528

महिलाएं आदिकाल से ही सशक्त थी- बिमला बाथम

साक्षात्कार

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण एवं अपराध सहित कई अन्य मुद्दों पर केशव संवाद पत्रिका के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी से नेहा कक्कड़ जी की खास बातचीत के कुछ अंश-

नेहा कक्कड़

देश और विशेष कर उत्तर प्रदेश में हो रहे महिला सशक्तिकरण को आप कैसे देखती है ?

— महिला आदि काल से सशक्त थी, घर की मुखिया भी महिलाएं होती थीं, बच्चे भी महिलाओं के नाम से जाने जाते थे, मैं तो ये कहूंगी की महिलाएँ उस काल में ज्यादा सशक्त थी। तब घर में महिलाओं का सम्मान था उनका हुक्म तो माना जाता था, परन्तु धीरे–धीरे महिलाओं के सम्मान में कमी आई और वो दयनीय स्थिति में पहुँच गयीं।

महिलाओं ने आज हर क्षेत्र में अपने वर्चस्व को स्थापित किया है, पर आप क्या समझती हैं कि और क्या होना बाकी है?

— हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के अनेक उदाहरण हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नेता प्रतिपक्ष जो एक बहुत बड़ा पद है उसे सुषमा स्वराज जी ने शोभित किया, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन जी रहीं। सुचेता कृपलानी जी, मायावती जी, जयललिता जी, और न जाने कितनी महिलाएँ जो राजनीति के शिखर पर पहुंची और अपनी सत्ता कायम की। आज की कैबिनेट की क्या बात करूँ हमारे पौराणिक समय का कैबिनेट भी महिलाओं के पास रहा है।

शिक्षा मंत्रालय — सरस्वती जी के पास, वित्त मंत्रालय — लक्ष्मी जी के पास है और रक्षा मंत्रालय शुरू से ही दुर्गा जी के पास रहा है। शास्त्रार्थ में गार्गी जी की कोई सानी नहीं थी। मध्य काल में रानी अहिल्या बाई होलकर, रानी लक्ष्मी बाई और आज सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसी महिलाएँ आज इसी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है।

बिमला जी आप भी हमारे पाठकों के लिए इसी सशक्तिकरण की मिसाल हैं और आप उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने आने वाली ग्रामीण परिवेश की और शहरी परिवेश की महिलाओं की समस्याओं में आप कितना अन्तर देखती है?

— अभी अंतर तो काफी देखने को मिलता है फर्क है भी, ग्रामीण इलाकों में अभी पर्दा प्रथा है, अभी ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में उतनी मुखरता भी नहीं है जितनी शहर की महिलाओं और लड़कियों में देखी जाती है। इतनी जागरूकता के बाद भी अभी गांव की महिलाओं को महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है, पर अब समय तेजी से बदल रहा है, हमारी सरकार एक–एक गाँव तक सूचना क्रांति पहुँचा कर उन्हें भी देश की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।

जब से योगी सरकार प्रदेश में आयी है, तभी से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का ग्राफ गिरा है पिछले कुछ सालों में। सरकार आगे इस दिशा में क्या कदम उठा रही है?

— मिशन शक्ति अभियान योगी सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, और इसे पूरे प्रदेश में आशातीत सफलता मिली भी है। मिशन शक्ति में तीन बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वालम्बन। पहले हम बात करे महिला सुरक्षा की तो ऐंटी रोमियो स्क्वाड बना, पुलिस महकमें में भय व्याप्त हुआ, कि महिलाओं की समस्याओं को नजरअंदाज करना परेशानी का सबब बन सकता है और आज आप इसका परिणाम देख सकती हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं और युवतियों के लिए कितना सुरक्षित हो गया है और क्राइम का ग्राफ भी बिलकुल रसातल पर आ गया है।

महिला आयोग महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी और सरकार के द्वारा चलायी जाने वाली अन्य योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने लिए क्या कर रहा है ?

— योजनाएँ तो केन्द्र और प्रदेश सरकार की अनेक है पर आज समस्या उनके क्रियान्वयन की आती है। सरकार ने आंगनवाड़ी और आशा बहनों को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ किया है और इसका परिणाम बहुत सकारात्मक आ रहा है। आंगनवाड़ी और आशा बहनों की पहुँच घर–घर तक है, और वे मोदी जी और योगी जी की मात्र शक्ति के उत्थान के लिए बनायी योजनाओं को महिलाओं और उनके परिवारों तक बहुत ही सरल और कारगर तरीके से पहुँचा रही है। और रही बात सम्मान की, तो जब सुरक्षा महिलाओं को मिल जाएगी तो सम्मान अपने आप ही आ जाएगा। आप केन्द्र सरकार की योजनाएँ देखिए, उज्ज्वला, हर घर शौचालय, आवास आदि इन सभी को महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। और अब हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी तो मात्र शक्ति को केन्द्रित कर योजनाएँ देते हैं।

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर आपकी क्या राय है?

— ये बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मेरे यह मानना है कि 18 साल की उम्र कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना तो बच्ची की पढ़ाई लिखाई ही परिपूर्ण होती है और ना ही मस्तिष्क परिपूर्ण होता है। 21 साल की उम्र में वह अपने निर्णय लेने में सक्षम

ISSN No. 2581-3528

हो जाती है, और अपने जीवन की दिशा तय करने के लायक हो जाती है। दूसरी बात लड़की का शरीर भी परिपक्व हो जाता है। तो जब उसकी शादी होती है तो उसपर और उसकी आने वाली संतानो पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार के इस कदम का पूरे भारत वर्ष की महिलाएँ और युवतियों दिल खोलकर स्वागत कर रही है।

क्या आपको लगता है कि ये फैसला बराबरी के अधिकार को सुरक्षित करता है?

– बिलकुल, अगर हम हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की बाराबरी का अधिकार दे रहे हैं इस मामले में भी बराबरी ही है।

मुख्यमंत्री सुमंगल कन्या योजना कैसे महिला के लिए वरदान साबित होगी ?

– मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल कन्या योजना बच्चियों के लिए एक बहुत ही लाभदायक और अच्छी योजना है। प्रदेश के जिस घर में बेटी पैदा होती है उसके जन धन खाते में हो हजार रुपए सरकार जमा करवा देती है, और जब बच्ची का टीकाकरण होता है 1 हजार, और जब वह पहली कक्षा में आती है तब 2 हजार रुपए, फिर जब वो छटी में होती है तब दो हजार और जब नवी में होती है तब तीन हजार और जब वो बारहवी कर लेती है, तब उसे 5 हजार रुपये मिलते हैं तो कुल मिलाकर 15 हजार रुपए मिलते हैं। ये योजना ऑनलाइन है और आंगनवाड़ी कार्यकताओं से इसके लाभ के बारे में जानकरी प्राप्त की जा सकती ह।

सबला महिला, आत्मनिर्भर महिला, इस दिशा में यू.पी. महिला सामर्थ्य योजना कितनी कारगर साबित हो रही है?

– महिला आत्मनिर्भरता और, महिला स्वावलंबन में भारत सरकार अनेक स्कीम चला रही है। आज महिलाएं ना किसी से कम है और ना नवोउन्मेषण में किसी से पीछे। आज जब कोई महिला हमारे पास कोई आयडिया लेकर आती है तो हमारे पास, स्टार्ट अप इंडिया, कौशल विकास, डिजीटल इंडिया आदि योजनाएं है जिसमें महिलाओं की रुचि के हिसाब से सरकार उन्हें ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाती है और उस काम की बारीकियां सिखा कर काम भी खुलवाया जाता है, और अगर महिला या युवती की आयु सीमा पूरी नहीं हुई है तो उसे उसी क्षेत्र में नौकरी भी मिल जाती है।

स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप का कितना योगदान समझती है, आप महिलाओं के विकास में ?

– स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सरकार इन्हें भरपूर सहायता कर रही। ये समूह चाहे लघु उद्योग लगा कर कार्य करें या महिलाओं को तकनीकि सहायता प्रदान कर उन्हें कोई काम स्थापित करवाएं। सरकार हमेशा इनको पूरी सहयोग करती हैं और योगी सरकार की सबसे सफल योजना रही है ओ.डी.ओ.पी., यानी वन डिसट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें आप देखें महिलाओं की भागीदारी कितने व्यापक स्तर पर है और मुझे इस बात पर बहुत हर्ष है कि ये भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है।

आप हमारी देश प्रदेश की बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी ?

–पहले तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और मेरी सभी से यह विनती है कि सभी स्वस्थ्य व सुरक्षित रहे करोना महामारी से। सब अपने परिवार को बचा कर रखें, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करें और मैं महिलाओं से ये अपील करूंगी कि वे अपनी शक्तियों को पहचाने, और अपने हुनर को समाज व विश्व के सामने लाएं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि समाज उन्हें सम्मान देगा और उनके सपनों को मंजिल जरूर मिलेगी। आपका प्रयास जब पूरे मन से किया गया होगा तो आपको दुनिया में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है और आखरी बात कि महिलाएं बिना भय और झिझक के आगे बढ़ें पर परिवार और समाज को साथ लेकर। ■

ISSN No. 2581-3528

योगी सरकार में कृषि विकास व किसानों का सम्मान

मृत्युंजय दीक्षित

देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और राज्य की अर्थवयवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ कृषि है। जब से 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी उसके बाद डबल इंजन की सरकार में किसानों की आय को दोगुना करने व उन्हें सम्मान देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश में कृषि विकास व किसानों के हित में लगातार काम किया जा रहा है।

प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा चुनावों के ऐलान के ठीक पहले किसानों को एक बड़ी राहत और खुशखबरी देते हुए सिंचाई के लिए बिजली की दर आधी कर दी है। सिंचाई के लिए निजी नलकूप की वर्तमान बिजली दर में सरकार ने 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार ने इस कदम के माध्यम से किसानों को बड़ा उपहार दिया है। इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जायेगा। बिजली की दरों में कटौती करने के लिए सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रूपये उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुदान देना पड़ेगा। देश के दूसरे कई राज्यों मे जहां सिचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है वहीं प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप की दर दो रूपये से छह रूपये यूनिट तक है।

योगी सरकार ने चुनाव से पहले ही किसानों के नलकूप की बिजली दर को 50 प्रतिशत कम करने का बड़ा दांव चल दिया है। सरकार का निर्णय आने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बहुत से कृषि संगठनों ने किसानों के बिजली कनेक्शनों के बिल में छूट की मांग की थी जिस पर सरकार ने बिल आधा करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने वाला होगा।

वैसे भी जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से किसानों के हित व उनके सम्मान के लिए तथा कृषि विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद किसानों की आय दोगुना करने के प्रयासों में भी और तेजी आयी है। विगत साढे चार वर्षों में प्रदेश में कृषि उत्पादन और किसानों से अनाज खरीद का रिकार्ड बना है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी लगभग दोगुनी बढ़ोत्तरी की गयी है।

2017 में प्रदेश भाजपा ने किसानों के लिए जो संकल्प लिया था वह साढ़े चार वर्ष में पूरा हो चुका है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रूपये के ऋणमोचन से शुरू हुआ सिलसिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना से लेकर रिकार्ड कृषि उत्पादन व प्रदेश में सबसे ज्यादा अनाज खरीद तक जारी है। खेती को तकनीक के साथ जोड़कर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास जारी है। योगी सरकार ने 45.74 लाख गन्ना किसानों को एक लाख 40 लाख करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। यह बसपा सरकार से दोगुना और सपा सरकार के कार्यकाल में किये गये गन्ना भुगतान के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक है।

प्रदेश में कृषि उत्पादन जो 2014—15 में 389.28 लाख मीट्रिक टन था वह 2020—21 में बढ़कर 624.19 लाख मीट्रिक टन हो गया है। कोरोना महामारी व लाकडाउन जैसी अति विषम परिस्थितियों के बीच किसानों व प्रदेश की यह सफलता स्वर्णिम है। 2021 से प्रदेश कोरोना महामारी की विपदा को झेल रहा था और फिर उसके बाद तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमारे अन्नदाता किसानों ने अन्न और सब्जियां आमजन को उपलब्ध कराई हैं। विगत साढे चार वर्षों में उप्र ने खाद्यान्न उत्पादन में भी नया रिकार्ड बनाया है। प्रदेश में अब तक 13,7,891 करोड़ रूपये मूल्य का गन्ना भुगतान कराया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019—20 में संचालित सभी चीनी मिलों से शत—प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। कोरोना महामारी के काल में भी 119 चीनी मिलों का संचालन किया गया जो अभूतपूर्व है। वहीं 91 चीनी मिलों को लाकडाउन में सेनिटाइजर बनाने का लाइसेंस दिया गया। गन्ना मिलों द्वारा 1500 करोड़ की बिजली का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया है। गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रदेश को पहला स्थान मिला है। पिपराइच, गोरखपुर में 5000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल शुरू हो चुकी है। एक समय वह भी था जब प्रदेश में चीनी मिलों को बेचा जा रहा था जिसमें बसपा सरकार का कार्यकाल एक काले कार्यकाल के रूप में याद किया जायेगा। जब बहिन मायावती के कार्यकाल में 11 चीनी मिलों का बेचने का सौदा हुआ और उसमें घोटाला हो गया था।

प्रदेश में कृषि विकास हेतु उठाये गये कदम : प्रदेश में 2017 में योगी सरकार का गठन होने के बाद साढ़े चार वर्षों में किसान हितैषी व कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये गये। राज्य सरकार ने नयी—नयी योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभान्वित किया। सरकार की ओर से हर स्रोत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गयी। हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गयी। हर खेत को उपजाऊ व स्वस्थ बनाने के लिए मृदा परीक्षण अभियान तेज गति से चलाया गया जिसका परिणाम दिखायी पड़ रहा है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को अच्छी किस्म के बीज एवं खाद उपलब्ध कराये गए। मिलियन फार्मर्स स्कूल पहल के माध्यम से किसानों को बेहतर तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया।

सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेंहू ,गन्ना, आलू उत्पादन में प्रदेश नंबर वन हो गया है।

गेहूं उत्पादन व खरीद में बना रिकार्ड : प्रदेश सरकार ने किसानों को बीज, पानी एवं उर्वरक समय पर प्रदान किया जिसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर वन हो गया है। वर्ष 2012—17 में जहां गेहूं उत्पादन 288.14 लाख मीट्रिक टन था जो योगी सरकार के साढ़े चार वर्ष की अवधि में यह बढ़कर 369.47 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अब तक 209.67 मीट्रिक टन

ISSN No. 2581-3528

गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वर्तमान सरकार के साढ़े चार वर्ष की कार्य अवधि में ही 43,75,574 कृषकों को 36,405 करोड़ रूपये गेंहू मूल्य का भुगतान किया गया जो एक रिकार्ड है।

आलू उत्पादन में नंबर वन : वर्ष 2021 में यूपी में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ। यूपी देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहां देश के कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत आलू पैदा होता है। करीब 61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोया जाता है जिसमें विगत वर्ष 147.77 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ। अब यूपी में आलू की खेती किसानों के लिए पूरी तरह लाभ का सौदा होने लग गयी है। कारण यह है कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में लगातार फैसले लिये हैं। सरकार खेत की तैयारी से लेकर बाजार तक किसानों के साथ है। उद्यान विभाग ने गांव–गांव जाकर किसानों को आलू की उन्नत तरीके से खेती की जानकारी दी।

दूध उत्पादन में नंबर वन : चार वर्षों में यूपी दुग्ध उत्पादन में भी नंबर वन हो गया है। प्रदेश में 2016–17 में दुग्ध उत्पादन 277.697 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ था अब यह 2020–21 में बढ़कर 318.630 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रीन फील्ड डेयरियों की स्थापना करने की शुरूआत की है। ये डेयरियां कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, कन्नौज, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद में लगायी जा रही हैं।

सरकारी मेहनत की बदौलत डेयरी उद्योग भी फल–फूल रहा है। दूध के कारोबार को यूपी में अलग पहचान मिली है। अब गांवों में पहले की संख्या में अधिक लोग गोवंश पालकर दूध को बेचने का काम कर रहे हैं। डेयरी मिलों को प्रोत्साहन दिये जाने से राज्य में रोजगार के नये अवसर प्रदान किये हैं। आज दुग्ध उत्पादन में भी यूपी नंबर वन है और इससे प्रभावित होकर ही 8 कंपनियों ने 172 करोड़ का निवेश किया है।

उर्वरक वितरण : खरीफ फसलों की बोआई के समय डीएपी उर्वरक की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ने के कारण प्रति बोरी मूल्य 2400 रुपये हो गया था। केंद्र द्वारा 500 रूपये प्रति बोरी अनुदान प्रति बोरी से बढ़ाकर 1200 रूपये कर दिया गया इससे किसानों को पूर्व की भांति 1200 रूपये प्रति बोरी की दर पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध हुई। दानेदार यूरिया के स्थान पर इफ्को द्वारा विकसित नैनो तरल यूरिया कृषकों को उपयोग के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

जैविक खेती को बढ़ावा : जैविक खेती को बढावा देने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 36 जनपदों में 585 क्लस्टर के 11,700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु 35 जनपदों के 38,670 हेक्टैयर क्षेत्रफल की तीन वर्ष के लिए 197 करोड़ रुपये की कार्ययोजना केंद्र सरकार को प्रेषित की गयी है।

हिंदी में भी होगा कृषि अवसंरचना निधि का पोर्टल : भारत सरकार द्वारा कृषि अवसरंचना निधि की स्थापना की गयी है जिससे कृषक अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा फार्मगेट एवं समेकन केंद्र (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पाद संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, मंडी समिति, एफपीओ) के वित्त पोषण के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा कृषि अवसंरचना निधि का पोर्टल अब हिंदी भाषा में भी होगा जिससे अधिक से अधिक किसान लाभ ले सकेंगे।

योगी सरकार ने शुरू की आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना की शुरूआत की है। 722.85 करोड़ रुपये की योजना से किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े 27 लाख से अधिक किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सरकार किसानों को खेत से लेकर बाजार तक हर स्तर पर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राशि खर्च करेगी। सरकार ने किसानों की आय बढाने के लिए हर ब्लाक में कम से कम एक एफपीओ स्थापित करने का फैसला लिया है। वर्तमान में प्रदेश के 824 ब्लाक्स के 408 ब्लाक्स में कुल 693 एफपीओ का गठन किया गया है।

प्रदेश में कृषक दुर्घटना योजना का विस्तार : योगी सरकार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना को विस्तार दिया गया है। पहले इसमें केवल सिर्फ किसान को ही लाभ मिलता था लेकिन अब किसी तरह की दुर्घटना होने पर किसान परिवार के कमाऊ सदस्य ओ बटाईदार को भी शामिल किया गया है। ऐसे किसी व्यकित की दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये की राशि उनके परिवार को प्राप्त होगी जो किसान आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो पाये हैं उन्हें मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना में कवर दिया जा रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत 2021 –22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रदेश की योगी सरकार का हर बजट गांव, गरीब और किसान को ही समर्पित रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर घर को नल, हर खेत तक पानी, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क, हर गांव को डिजिटल बनाने के साथ ही हर हाथ को काम देने का हरसंभव और सफल प्रयास किया है। यही कारण है कि आज कृषि के क्षेत्र में कोरोना महामारी व तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी लगातार विकास कर रहा है। प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो रही है और वह सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है और देश के दूसरे राज्यों की कमियो को भी पूरा कर रहा है। आज प्रदेश में हरित क्रांति से लेकर नयी दुग्धक्रांति तक हो रही है। चारों ओर विकास हो रहा है। यह संभव हुआ है प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रदेश के दो करोड़ 53 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिये जा रहे 6 हजार रूपये वार्षिक के कारण आज प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है क्योंकि हर नहर जल से भरी हुई है और उन्हें खाद, बिजली, पानी मिल रहा है।

(लेखक स्तम्भकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

लो फिर बसंत आया, मन में उमंग छाया

नीलम भागी

विभाजन के बाद मेरे पिताजी का लाहौर से स्थानान्तरण प्रयागराज हुआ तो मेरी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने वाली दादी, गंगा जी के कारण बहुत खुश थी। पंजाब में सभी रिश्तेदार इसलिये खुश थे कि जब भी वे हमारे यहां आयेंगें तो गंगा जी जायेंगे। अम्मा बताती हैं कि आजादी के बाद वहां जो पहला कुंभ 1954 में आया तो सब रिश्तेदार पंजाब से प्रयागराज बड़े हिसाब किताब से आये थे। जिसमें मौनी अमावस, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और कुंभ संक्रान्ति का उत्सव भी आ गया। इन उत्सवों में नदियों में स्नान करने की परंपरा है। कोई भी संस्कार कर्म करने से पहले लोटे में जल लेकर गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, इन सातों नदियों का आहवान किया जाता है। और प्रयागराज में तो इनमें से तीन नदियों की त्रिवेणी है। कोई शुभ दिन हो, चलो, गंगा जी नहाने। अब मेरी ठेठ पंजाबी ब्राह्मण दादी, भोजपुरी गीत गातीं थीं। सत्तू, भूजा या चबेना उनका फास्ट फूड हो गया था। अपनी अनपढ़ सखियों के साथ, माघ मेले (वार्षिक मिनी कुंभ) जातीं। वहां से लोक गीत सुनकर आतीं और घर आकर गातीं। शब्द चाहे गलत हों पर स्वर से नहीं भटकती थीं और उनकी अनपढ़ सखियां कोरस बहुत अच्छा देती थीं। तभी तो बचपन में मेरी मैमोरी में फीड हो गया और आज लिखते समय धुन समेत गुनगुना रहीं हूं। मसलन –

इधर बहै गंगा, उधर बहै यमुना, बिचवा में सरस्वती की धार।
माघवा महिनवा, त्रिवेणी के तट पर, जाइबो मैं करिके सिंगार।
ओ गंगा तोरी लहर, सबही के मन भायी'.... 2
तीर्थराज का जान महातम, ऐसो ही भज लै न रामा, ऐसो ही भज लै न।
अरे गंगा गोता खाय खाय के, हमहूं तर गयो न।
हो धन धन गंगे मात, सबही कै मन भाई।हो गंगा तोरी.....

हमारे अवतारों की जन्मभूमि प्राचीन नगर, महानगर या तीर्थस्थल नदियों वाले शहरों में है। र्तीथस्थल हमारी आस्था के केन्द्र हैं। यहां जाकर मानसिक संतोष मिलता है। देश के कोने–कोने से तीर्थयात्री माघ मेला में आते हैं। सभी तीर्थ भी अपने राजा से मिलने प्रयागराज, माघ में आते हैं। इसलिए श्रद्धालु भी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक यहां रहना, अपना सौभाग्य मानते हैं। एक ही स्थान पर समय बिताते हुए प्रदोष, माघी पूर्णिमा, गुरु रविदास जयंती, जानकी जयंती, छत्रपति शिवाजी जयंती, दयानंद सरस्वती जयंती मिलजुल कर मनाते हैं। अपने प्रदेश की बाते करते हैं और दूसरे की सुनते हैं। कुछ हद तक देश को जान जाते हैं। उनमें सहभागिता आती है। अपने परिवेश से बाहर नये परिवेश में कुछ समय बिताते हैं। कुछ एक दूसरे से सीख कर जाते हैं, कुछ सिखा जाते हैं। मानसिक सुख भी प्राप्त करते हैं। धर्म लाभ तो होता ही है।

मौनी अमावस को मौन धारण कर गंगा जी या अपने आसपास नदी न होने पर वैसे ही स्नान करके तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला वस्त्रादि का दान करते हैं। मौन व्रत भी तो मन को साधने की यौगिक क्रिया है। इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस उत्सव में ठिठुरती ठंड में अध्यात्मिक आनन्द मिलता है।

फूली हुई है सरसों और धरती तो फूलों के गहनों से सजने लगी है, ऋतुराज बसंत के स्वागत में। यानि 'बसंत पंचमी का उत्सव' सब ओर रंग और उमंग। पीले कपड़े पहनना, पीले चावल या हलुआ बनाना, खाना, खिलाना और परिवार सहित सरस्वती पूजन करना। इस दिन बिना साहे के विवाह संपन्न किए जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बच्चे का अन्नप्राशन यानि पहली बार अन्न खिलाने का संस्कार कर सकते हैं। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य बच्चे को खीर चटाता है। बसंत पंचमी के बाद से बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरु किया जाता है। वैसे बच्चे को छ महीने का होने पर पहले ही अन्न देने लगते हैं। पर अन्नप्राशन संस्कार बसंत पंचमी को कर लेते हैं।

बच्चे का तख्ती पूजन (अक्षर ज्ञान) करते हैं। सरस्वती पूजन के बाद तख्ती पर हल्दी के घोल से बच्चे की अंगुली से स्वास्तिक बनवाते हैं। परिवार बोलता है– **गुरू गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई।**

और बच्चे की स्कूली शिक्षा शुरु होती है। पूर्वांचल में बसंत पंचमी को होलिका दहन के लिए ढाड़ा गाढ़ देते हैं। फगुआ के बिना होली कैसी!! अब फगुआ, फाग, जोगीरा और होली गायन शुरु हो जाता है। जिसमें शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और लोकगीत हर्षोल्लास से गाए जाते हैं। प्रवासी घर जाने की तैयारी शुरु कर देते हैं। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, शाह बिहारी मंदिर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और बरसाना के राधा जी मंदिर में ठाकुर जी को बसंत पंचमी के दिन पीली पोषाक पहनाई जाती है और पहला अबीर गुलाल लगा कर होलिका दहन के लिए ढाड़ा गाड़ा जाता है और बसंत पंचमी से फाग गाने की शुरुआत होती है। देश विदेश से श्रद्धालु ब्रजमंडल की होली में शामिल होने के लिए तैयारी शुरु कर देते हैं। बसंत पंचमी से ब्रज में चलने वाले 40 दिन के उत्सव पर, होलिका दहन को अनोखा नज़ारा देखना अपने सौभाग्य की बात है, ऐसा माना जाता है।

खिचड़ी मेला गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर गोरखपुर (जिले का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर है) से मकर संक्राति को शुरु होता है जो एक महीने से अधिक समय फरवरी तक चलता है। मकर संक्राति को तड़के से खिचड़ी चढ़ाई जाती है। किसान अपनी पहली फसल की खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाइनों में लगे होते हैं। इस प्रशाद की खिचड़ी को मंदिर की ओर से बनाया जाता है और विशाल मेले के साथ, मंदिर में खिचड़ी का भंडारा चलता है। रविवार और मंगलवार के दिन खास महत्व होता है। मेले में झूले और हर तरह के सामान, खाने पीने की दुकानें लगी रहती हैं। गुरु गोरखनाथ के खिचड़ी मेले में कोई भूखा नहीं रह सकता। खिचड़ी का प्रशाद खाओ और मेले का आनन्द उठाओ। देश के बड़े आयोजनों में यह मेला है।

माघ पूर्णिमा को काशी में जन्में संत रविदास की जयंती पवित्र नदी में स्नान करके उनके रचे पदों दोहों को कीर्तन में गाया जाता है। उनका जीवन बताता है कि भक्ति के साथ सामाजिक, पारिवारिक कर्त्तव्यों को भी निभाना चाहिए। उनका कहना था कि 'मन चंगा तो कठौती में गंगा'

ब्राहम्ण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण

हर नदी वहां के स्थानीय लोगों के लिये पवित्र है और उनकी संस्कृति और उत्सवों से अभिन्न रूप से जुड़ी है। नदियों को माँ कहा जाता है। जैसे माँ निःस्वार्थ संतान का पोषण करती है, वैसे ही नदी हमें देती ही देती है। जीवनदायनी नदियों को लोग पूजते हैं, मन्नत मांगते हैं। वनवास के समय सीता जी ने भी गंगा मैया पार करने से पहले, उनसे सकुशल वापिस लौटने की प्रार्थना की थी। इसलिए जानकी जयंती पर श्रद्धालु पवित्र नदी का पूजन भी करते हैं। यही हमारे उत्सवों की मिठास है जिसमें प्रकृति भी हमारे साथ है। **(लेखिका)** ■

ISSN No. 2581-3528

असहिष्णु वैश्विक बौद्धिक सक्रियतावाद और भारतीय सांस्कृतिक पहचान

डॉ. अक्षय कुमार सिंह

भारत आज बदलाव के अप्रतिम दौर में है। सुदृढ़ भविष्य के सृजन के पथ में दृश्य और अदृश्य चुनौतियां अस्वयंभावी हैं। यद्यपि आतंरिक चुनौतियों के जटिल स्वरुप ने वर्तमान भारतीय राजनीतिक शिल्पकारों की संकल्प–शक्ति को परीक्षित किया हैं परन्तु इन चुनौतियों के अर्न्तसम्बन्ध वैश्विक संरचनाओं एवं वैचारिकी के अभिमिश्रित परन्तु विकृत जटिल फलक के साथ हैं, जिसने चुनौतियों के सम्पूर्ण स्वरुप को और पेचीदा कर दिया हैं। किसी भी राष्ट्र के उन्नयन की सार्थकता इन तत्वों के बेहतर समायोजन पर अवलम्बित हैं। अस्तु, हमारे (शिक्षाविदों) समक्ष वैश्विक बौद्धिक सक्रियतावाद की आतंरिक चुनौतियों के साथ आभ्यन्तरिक सह–सम्बन्ध भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता को विश्व–पटल पर किस तरह से चोटिल कर रहा हैं इसका परीक्षण नितांत आवश्यक हैं। आवश्यक हैं इस प्रश्न का परीक्षण की विगत कुछ वर्षों में किन तरह की ताकतें विश्व समाज में भारत का विकृत चित्रण कर रहीं हैं और उनके इन प्रयासों के पीछे निहित स्वार्थ क्या हैं?

इनके पीछे मुख्यतया दो तरह की ताकतें हैं– (1) भू–रणनीतिक और भू–राजनितिक स्वार्थों से प्रेरित राष्ट्र–राज्य जिनकी भारत ने गत वर्षों में यथोचित प्रशोधन किया है, जिन्हें ऐसा होने का आभास भी नहीं था, और वर्तमान में उनके हर एक अभिकल्पित षड्यंत्र का प्रति–उत्तर मजबूती से प्रस्तुत कर रहा हैं। उन तत्वों के विद्वेष, विग्रह, वैमनष्य के कुंठा ने उन्हें वैकल्पिक रणनीति के तरफ प्रेरित किया हैं जिससे भारत की चुनौतियां और गहरी हुईं हैं। (2) ऐसे तत्व जिन्हे स्वयं नव–मार्क्सवादी (जुर्गेन हाबरमास, मैक्स हरखाइमर) सिविल सोसाइटी या स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसन के रूप में वर्णित करते हैं। वो तत्व आतंरिक या वाह्य फलक पर तथाकथित बौद्धिक, राजनैतिक, मीडिया, सामाजिक आंदोलनकारी, एवं नारीवादी वर्गों से सम्बद्ध हैं तथा भारत की वर्तमान परिपेक्ष्य में समाजार्थिक एवं विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल की विद्रूप तस्वीर पेश करने की दृष्टता में संलिप्त हैं।

असहिष्णु वैश्विक बौद्धिक सक्रियतावाद उपर्युक्त वर्णित दोनों तत्वों का संश्लेषण हैं। हाल के दिनों में पूर्व एवं पश्चिम के तथाकथित बुद्धजीविओं का बौद्धिक समागम 'डिस्मेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस' के रूप में गत सितम्बर महीने में आयोजित हुआ. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन हुए इस सम्मेलन को 'अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के 53 विश्वविद्यालयों के 70 से अधिक केंद्रों, इंस्टीट्यूट्स, कार्यक्रमों और अकादमिक विभागों का समर्थन प्राप्त था' और इसे 'हार्वर्ड, स्टेनफर्ड, प्रिंस्टन, कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस, बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवीनिया और रटजर्स जैसे विश्वविद्यालयों का सहयोग भी'। इस सम्मलेन से तथाकथित विद्वानों और कुछ सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा लगातर भारत विरोधी कोशिशों को यथार्थ रूप देने का प्रयास था जिसमे प्रस्तावित उद्देश्य था की 'हिंदुत्व भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, भारत के दलितों के खिलाफ है और भारत की महिलाओं के खिलााफ है। हम हिंदुत्व की आलोचना कर रहे हैं'।

मंशा साफ हैं। यद्यपि यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण होगा कि उन्हें हिंदुत्व का वास्तविक अर्थ नहीं पता। परन्तु वैश्विक स्तर पर जिस अफसाने (नैरेटिव) को स्थापित करने की कोशिश की जा रही हैं उसके दो महत्वपूर्ण आयाम हैं– प्रथम, भारत अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रयासों को जीवंत कर रहा है, विश्व की सबसे प्राचीन एवं सतत् सांस्कृतिक विरासत को विश्व के फलक पर उदघाटित करने का संतुलित, संगठित पर संयमित कोशिश विगत कुछ वर्षों से हो रही है। यह श्रेष्टतम विरासत अपनी वास्तविक विशिष्टताओं के साथ विश्व–समाज से सुपरिचित हो इसके लिए बहुमुखी यत्न जारी हैं। यह प्रयास इतिहास के गर्व में छिपे वास्तविक तथ्यों को उदघाटित कर, विश्लेषित कर प्रसारित करने के रूप में हो रहा हैं। पिछले दशकों और शताब्दियों में भारतीय संस्कृति की भ्रांतिपूर्ण, मिथ्यापरक और नकारात्मक विवेचनाओं के लिए जो एक खास बौद्धिक–वर्ग जिम्मेदार था उनकी एक श्रेणी उन्ही भूमिकाओं पर नए स्वरुप में लिप्त हैं। विदित हो कि उपर्युक्त सम्मलेन की सूत्रधारों में एक रुटजर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, ऑड्रे तृस्के, जिन्होंने मिथ्यापरक प्रयास के तहत भ्रांतिपूर्ण तरीके से रोबर्ट गॉडमैन के रामायण को गलत उद्धृत कर राम को नारीविद्वेषी बताया था, जिसका गॉडमैन ने खुद खंडन किया था। अपनी शास्त्रीय अनिष्ठा के लिए कलंकित बौद्धिक–जन इन तरह के प्रयोजनों के सूत्रधार हों तो यह साबित होता हैं उनकी कुत्सित मंशा स्वस्थ्य बौद्धिक संगम नहीं वरन् भारतीय संस्कृति को अपमानित करना था। द्वितीय, ऐसे प्रयासों से भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरुप को संकुचित कर राजनीतिक–धारा से आबद्ध करना भी प्रतीत होता है। हिंदुत्व को राजनीतिक संकल्पना के रूप में स्थापित करना अकादमिक ओछापन है और यह सुविचारित और कुत्सित भी। अपने विजयादशमी के ओजपूर्ण उदबोधन में सरसंघचालक माननीय भागवत जी ने कहा – "हिन्दुत्व ऐसा शब्द है, जिसके अर्थ को पूजा (धर्म) से जोड़कर संकुचित किया गया है। यह शब्द अपने देश की पहचान को, आध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य और समस्त मूल्य सम्पदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला शब्द है।" यक्ष प्रश्न यह हैं कि वैश्विक बौद्धिक वर्ग द्वारा हिंदुत्व के संकुचित विश्लेषण की कुंठा, हिंदुत्व के सांस्कृतिक विस्तार और वैश्विक स्वीकृति को कितना प्रभावित करेगी? उत्तर हैं, बिल्कुल नहीं। विज्ञान के थ्रेशोल्ड डिस्प्लेसमेंट सिद्धांत से सहमत होकर यह स्वीकारना होगा की भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकारोक्ति अवश्यंभावी हैं और सन्निकट भी।

(लेखिक गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में फैकल्टी हैं)

ISSN No. 2581-3528

आधी आबादी की भागीदारी

मोनिका चौहान

पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। अनेक राज्यों में हुए विभिन्न चुनावों में महिलाएं पुरुषों के समान मतदान कर रही हैं, जबकि कई स्थानों पर वे पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान कर रही हैं। इसके अलावा महिलाएं अपनी राजनैतिक पसंद को लेकर भी स्वायत्त हो रही हैं किंतु यह प्रचलन भी शहरी क्षेत्र की तथा शिक्षित महिलाओं में अधिक देखा गया। उत्तर प्रदेश चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है। गत 2017 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। 2017 में करीब 60 फीसदी पुरुषों ने और 63 फीसदी से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। भाजपा सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म करके मुस्लिम महिला वोट बैंक भी अपने पक्ष में कर लिया लेकिन चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या कम होना कहीं ना कहीं महिलाओं पर राजनीतिक मामले में अविश्वास जताता है।

जहां कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सरकार के नए मंत्रिमंडल में 9 महिलाओं को शामिल किया था वहीं दूसरी और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में जारी पहली सूची में महिलाओं को ना के बराबर प्रत्याशी घोषित करना निराशाजनक है। प्रत्येक क्षेत्र में महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है वही राजनीति में भी इनकी भागीदारी निश्चित रूप से प्रतिनिधियों की दिशा व दशा परिवर्तित करने का दम व खम दोनों रखती है। बशर्तें उनकी शक्ति को समझकर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। जहां हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बेटियों को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी महिलाएं राजनीतिक दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। गत विधानसभा चुनावों में जीत प्राप्त करने वाले महिलाओं में भाजपा की सबसे ज्यादा महिलाएं थी। करीब 34 भाजपा महिलाओं ने अपनी जीत का परचम लहराया था इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की मात्र दो–दो तथा समाजवादी पार्टी और अपना दल से कुल एक एक महिला विधायक चुनी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए महिला सशक्तीकरण अभियान के चलते शहर से लेकर गांवों में महिलाओं में जागरूकता आयी उन्होंने पंचायत चुनावों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया और ग्रामीण जनता ने बड़ी संख्या में जीताया भी। पंचायतों में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा है। यूपी में इस बार ग्राम प्रधान के 58,176 पदों में से 31,212 पदों पर महिलाओं ने जीत हासिल की है।

ब्लॉक प्रमुख के पद पर 447 और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर 42 महिलाएं चुनाव जीती हैं गत कुछ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा दिया जाता रहा है।

योगी और मोदी सरकार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आये। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और तीन तलाक कानून यह सभी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार के द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है लेकिन राजनीति में महिला प्रत्याशियों की इतनी कम संख्या यह दर्शाती है कि अभी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को राजनैतिक तौर पर और सशक्त होने की आवश्यकता है। आधी आबादी की भागीदारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में हालांकि कम है लेकिन मतदाता के रूप वे अब स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है। महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव होता है।

आज महिलाएं बिना किसी डर के घर से निकल पा रही हैं और वे अपने आप को मजबूत व सशक्त महसूस कर रही हैं तो यह केवल योगी सरकार में संभव हो पाया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में महिलाएं स्वयं को सुरक्षित और सशक्त पा रही हैं और आर्थिक स्वायत्तता की तरफ अग्रसर है। तीन तलाक मुद्दा व उज्जवला योजना मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोलता है उन्हें सशक्त बनाता है। जिस प्रकार प्रधान बनकर महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं और गांव को सशक्त बना रही हैं उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी, उनका प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा।

(लेखिका शिक्षिका हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

क्या अब मथुरा की बारी है ?

रंजना मिश्रा

उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, वे दिन–रात प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने में लगे हुए हैं। इससे पहले की सरकार में प्रदेश में बेखौफ अपराधी दिनदहाड़े हत्या और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे व अराजकता फैलाते थे और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती थी, लेकिन जब से प्रदेश की बागडोर योगी जी ने संभाली, माफियाओं और अपराधियों की नाक में नकेल कसनी शुरू कर दी। अब अपराधियों का यह हाल है कि वे पुलिस के सामने खुद ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। महिलाएं भी अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी योगी जी भगवा वस्त्र में एक सन्यासी हैं, वे अपने कर्म योग द्वारा प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं।

योगी सरकार के शासन में धर्म और आस्था को भी पूरा सम्मान मिला है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों पर है और बनारस का तो कायाकल्प ही हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण करके अंतरराष्ट्रीय फलक पर काशी की एक नई तस्वीर पेश की गई है। हाल ही में योगी जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, 'अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का वादा पूरा किया गया और काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रुप से बन रहा है, फिर मथुरा–वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है।' इसके अतिरिक्त बीजेपी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है। हाल में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट करके इस ओर संकेत किया था और यूपी से बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तो 30 अगस्त 2021 को एक ट्वीट में मथुरा की ईदगाह मस्जिद का गुंबद और कृष्ण जन्मभूमि के केशवदेव के मंदिर के शिखर की तस्वीर एक साथ पोस्ट करते हुए लिखा था कि यह दृश्य मुझे शूल की तरह चुभता है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि यदि हिंदुओं के सपनों को कोई पूरा कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने से पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि जिस दिन फैसला आएगा, उस दिन खून की नदियां बहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आने के बाद पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहा।

जिस तरह अयोध्या में मुगल शासक द्वारा मंदिर का विध्वंस किया गया था, उसी तरह मथुरा में भी किया गया था। एक ओर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़वाए जाने की मांग हो रही है तो दूसरी ओर योगी जी भी जनसभाओं में निर्माण और विध्वंस का जिक्र कर रहे हैं। वे भगवान राम के साथ ही, भगवान कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं और दो बार प्रधानमंत्री मोदी को कृष्ण की मूर्ति भेंट कर चुके हैं। अलीगढ़ के बाद जेवर में भी योगी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को कृष्ण भगवान की मूर्ति उपहार में दी थी।

कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1991 में उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम पारित करके हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई थी। जब 1990 में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मथुरा और काशी को लेकर भी यह मांग उठने लगी कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा था कि ये दोनों ही मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। इसलिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को भरोसा दिलाने के लिए एक कानून पारित किया। इस कानून के मुताबिक यह प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 में देश में जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी, वही हमेशा बरकरार रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता। इस कानून के खिलाफ कोई व्यक्ति न तो अदालत में जा सकता है और ना ही इसे चुनौती दे सकता है। इसलिए मथुरा और काशी के मुकदमों में यह कानून भी एक बड़ा पेंच है। अर्थात् विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार के दम पर हिंदुओं के जिन धार्मिक स्थलों पर बलात् कब्जा किया गया था, उसे कांग्रेस सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्य ठहरा दिया गया। यह वास्तव में हिंदुओं के साथ एक बड़ी ज्यादती है और अब इस कानून को निरस्त किए जाने की मांग उठ रही है। वास्तव में जब स्वतंत्र भारत में इस देश की मूल संस्कृति के प्राण और मूल संस्कृति से जुड़े लोगों के आराध्य ही आजाद नहीं हुए, तो यह भारत की कैसी आजादी है? **(लेखिका)** ■

ISSN No. 2581-3528

स्वास्थ्य सुविधाओं का सुशासन

डॉ. विनीत उत्पल

दूरदर्शी नेतृत्व होने से किसी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे कम समय में बेहतर हो सकती है, यह उत्तर प्रदेश को देखकर समझा जा सकता है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकासशील सोच होने, परिवर्तनकारी योजनाएं तैयार करने और उन्हें युद्धस्तर पर अमलीजामा पहनाने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितना कार्य हुआ है, उससे आधा फीसदी कार्य आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ था। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्य को देखकर कहा जा सकता है कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुशासन है. जब पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजर रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सेवा किसी से छुपी नहीं थी. ऐसे हालात में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तंत्र ने दिन–रात कार्य किया, कोरोना पर काबू पाया, यह किसी से छुपा नहीं है।

45 मेडिकल कॉलेजों की तैयारी : प्रदेश के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां 1947 से लेकर 2017 तक सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आने वाले समय में प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज हो जायेंगे। इनमें से करीब 13 मेडिकल कॉलेज बन कर तैयार है और 16 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तैयार किये जा रहे हैं। साथ ही, प्रदेश में कुल 45 मेडिकल कॉलेज होंगे जहां 100 बिस्तर होंगे। गोरखपुर और रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तैयार हो रहा है।

इंसेफ्लाइट्स रोगियों के संख्या में आई कमी : स्वास्थ्य सेवाओं की और प्रदेश सरकार की सक्रियता के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों में महामारी मानी जाने वाली इंसेफ्लाइट्स रोगियों की संख्या में 56 प्रतिशत की कमी आई और इससे होने वाली मृत्यु में 90 प्रतिशत की कमी आई। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रत्येक रविवार को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 'मुख्यमंत्री आरोग्य मेला' का आयोजन शुरू किया गया, जहाँ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य जाँच और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया गया।

एक दिन में शुरू हुए पांच हजार स्वास्थ्य उपकेन्द्र : आजादी के बाद 74 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में 20 हजार स्वास्थ्य उपकेन्द्र थे और योगी सरकार ने एक ही दिन में 5 हजार स्वास्थ्य उपकेंद्रों की शुरुआत की। ये उपकेन्द्र स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों और पिछड़े जिलों में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के कुल पांच हजार नए स्वास्थ्य केन्द्रों से स्वास्थ्य योजनाओं को लागू कर आवश्यक चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा व पैरामेडिकल स्टाफ की भी उपस्थिति सुनिश्चित की गई। यहाँ मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, किशोर स्वास्थ्य, मधुमेह, रक्तचाप की जाँच, संचारी और गैर–संचारी रोगों के उपचार की व्यवस्था की गई। इसके अलावा, योग एवं व्यायाम, परामर्श, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएँ जैसी गतिविधियाँ भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने 15 बीएसएल–2 प्रयोगशाला एवं मां नवजात एप (मंत्र) का लोकार्पण भी जनता के लिए किया।

इज्जत घर से बची इज्जत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 2020–21 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश ने दस्त पर प्रभावी नियंत्रण किया है और दस्त के मरीजों के मामले या संक्रमण दर 15.6 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत रह गई है। स्वच्छता अभियान के तहत गाँव–गाँव में बनाये गए 'इज्जत घर' यानी शौचालय के कारण इसमें कमी आई. साफ–सफाई के प्रति लोगों के जागरूक होने से बीमारियों में कमी आई है और लोगों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हुआ है। लोगों में परिवार नियोजन के साधनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का कार्य उत्तर प्रदेश शासन ने किया है। यही कारण है कि परिवार नियोजन के साधनों की उपयोगिता 45. 5 प्रतिशत से बढ़कर 62.4 प्रतिशत हो गई है। संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा दिया गया है। पहले संस्थागत प्रसव 67.8 प्रतिशत था और अब यह बढ़कर 83.4 प्रतिशत हो गया। प्रजनन दर भी 2.7 से घटकर 2.4 पर आ गई है।

बाल स्वास्थ्य में आई जागरूकता : बाल स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश में जागरूकता आई है। पहले छह माह तक की उम्र के 41.6 प्रतिशत बच्चे स्तनपान करते थे और अब यह बढ़कर 59.7 प्रतिशत हो गया है। प्रसव पूर्व जांच कराने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। पहले 26.4 प्रतिशत महिलाएं ही यह जांच करवा रही थी लेकिन अब यह प्रतिशत 42.4 हो गया है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में कहा था कि उत्तर प्रदेश में 3,621 डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन राज्य में केवल 1,344 डॉक्टर काम कर रहे हैं। राज्य के 942 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बिजली, पानी की नियमित सप्लाई, सभी मौसम में पहुंचने लायक सड़क के बगैर काम कर रहे हैं। बावजूद इसके, प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के जरिये जनता को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा रही है, चिकित्सकों की भर्ती कर रही है, तो आने वाले समय में कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के युवा नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा। **(लेखक शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में जनसंचार विभाग स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म इंटरटेनमेंट में सहायक प्राध्यापक हैं)** ■

ISSN No. 2581-3528

दिनचर्या

डॉ. सुनेत्री सिंह

हमारे ऋषि और मनीषियों का मानना है कि मनुष्य का जन्म जन्म जन्मान्तरों में – किये गये पुण्यों का परिणाम होता है। पूर्व में किये गये सुकृत कर्मों के बिना मनुष्यत्व प्राप्त नहीं हो सकता है और मनुष्य जीवन को ही अत्यन्त दुर्लभ और महत्वपूर्ण माना गया है। यह सभी स्वीकार करते है कि मनुष्य जीवन अन्य सभी जीव जन्तुओं से सर्वथा उच्च है और मनुष्य जीवन में ही वह उन्नति कर सकता है। वह अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग करके अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकता है। लौकिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वस्थ मन और स्वस्थ तन की आवश्यकता होती है। आरोग्य की आवश्यकता होती है।

आरोग्य रक्षा मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में ही कहा गया है। "धर्मार्थकाममोक्षाणांमारोग्यमूलमत्तमम्" अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरूषार्थो के मूल में आरोग्य ही है। तात्पर्य यह है कि पुरूषार्थ चतुष्टय की सिद्धि तभी होती है। जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो मन और आत्मा प्रसन्न हो वह सही पथ पर अग्रसर हो। चरक संहिता में कहा गया है।

सर्वमन्यत्परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्। तदभावेहिभावानां सर्वाभावः शरीरिणाम् ।। (च० नि० 6/7)

अर्थात् संसार में सब कुछ छोड़कर स्वशरीर का पालन करना चाहिए। क्योंकि शरीर ही सभी सुख – दुःख के भोग का माध्यम है। चरक संहिता में अन्यत्र कहा गया है कि

''नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी स्वषरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत् ।।'' (च० सू० 5 / 103)

अर्थात् जिस प्रकार नगर स्वामी नगर तथा सारथी रथ की रक्षा में सदा तत्पर रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरूष को अपने शरीर की रक्षा में सदा तत्पर रहना चाहिए।

आयुर्वेद में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वस्थवृत्त का उल्लेख है। जिसके अन्तर्गत दिनचर्या, रात्रिचर्या तथा ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है कि दिनचर्या प्रातः काल ब्रह्ममुर्हुत में उठने से लेकर संध्या काल तक किये जाने वाले ऐसे सुव्यवस्थित कर्म जिससे स्वास्थ्य उन्नत अवस्था में बना रहता।

• **दन्त धावन** – प्राचीन काल में दन्तधावन के लिए नीम तथा बबूल आदि की लकड़ी का प्रयोग बताया गया था, किन्तु आजकल ब्रश का प्रयोग होने लगा है। फिर भी दन्तधावन के लिए आयुर्वेदिक दन्त मंजन ही प्रयोग करना चाहिए।

• **जिह्वा निर्लेखन**– दन्तधावन के पश्चात् जिह्वा निर्लेखन का क्रम

• **गण्डूष या गरारा**– दन्त धावन के पश्चात् शीतल जल से अथवा स्नेह (तिल – तैल) का गरारा करने का विधान आयुर्वेद शास्त्र में दिया गया है।

• **मुख प्रक्षालन**– गण्डूष के पश्चात् मुख एवं नेत्र प्रक्षालन करना चाहिए।

• **अंजन** – मुख प्रक्षालन के पश्चात् अंजन लगाना चाहिए। अंजन के प्रयोग से दृष्टि सम्यक् बनी रहती है।

• **नस्य** –आयुर्वेदाचार्यो ने प्रतिदिन नासाछिद्रों में स्नेह लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि प्रतिदिन नस्य करने से उर्ध्वजत्रुगत रोग नहीं होते है।

• **धूमपान** – औषधीय द्रव्यों को लेकर धूमपान करने का निर्देश आचार्यों ने दिया है। जिससे मस्तिष्क व गले के रोगों का नाश होता है।

• **व्यायाम एवं चंक्रमण**- इसके पश्चात् व्यायाम का क्रम आता है। जो व्यक्ति–व्यायाम करने में समर्थ हो उन्हें सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करना चाहिए तथा जो समर्थ ना हो उन्हें चंक्रमण (चहलकदमी) करना चाहिए।

• **क्षौर कर्म**- केश, नख, रोमापमार्जन को अत्यन्त आवश्यक एवं स्वस्थवृत्त की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं मानवोचित सौन्दर्य का कारक है।

• **अभ्यंग** – आयुर्वेद में अभ्यंग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अभ्यंग विशेष रूप से वातहर तथा वेदनाहर है। अभ्यंग जराहर तथा आयु को बढ़ाने वाला, त्वचा को सुन्दर बनाने वाला है।

• **शरीर परिमार्जन** – औषधीय चूर्ण या औषधीय कल्क आदि को शरीर पर लगाना परिमार्जन है। इससे त्वचा में स्थित जीवाणुओं का नाश होता है, तथा रोम छिद्र खुलते है।

• **स्नान** – नित्य प्रति स्नान रोगों का नाश करता है। यह निद्राहर है, तथा स्वेद, – खुजली का नाश करता है। ऋतुओं के अनुकूल जल से स्नान करना चाहिए।

• **वस्त्र धारण**– सदा निर्मल वस्त्र ही धारण करने चाहिए। निर्मल वस्त्र, हर्षकारक, प्रीतिवर्धक तथा उत्साह वर्धक होते हैं।

• **सन्ध्योपासना एवं ध्यान**- प्रतिदिन की दिनचर्या में सन्ध्योपासना का विशेष – महत्व है। इससे सद्प्रवृत्ति, बुद्धि, यश, कीर्ति तथा आत्मिक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है।

• **स्वाध्याय-स्वाध्याय**- द्वारा सद्ग्रन्थों का अध्ययन मनन करना तथा उन्हें अपने – जीवन में उतारकर स्वयं का जीवन उत्कृष्ट बनाना यह स्वाध्याय है। यह दिनचर्या का प्रमुख अंग है।

भोजन- आयुर्वेद के ग्रन्थों में आहार को अमृत कहा गया है तथा इसका–सेवन युक्ति पूर्वक करने का निर्देश दिया गया है। सुश्रुत संहिता में आहार को शरीर को पुष्ट करने वाला, बलकारक, देहधारण करने वाला आयु, तेज, उत्साह स्मृति देने वाला तथा अग्नि को बढ़ाने वाला कहा गया है।

इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों दिनचर्या का संक्षिप्त अध्ययन आपने किया अब स्वस्थवृत्त का दूसरा अंग रात्रिचर्या का संक्षिप्त वर्णन आयुर्वेद के ग्रन्थों के अनुसार निम्न है –

. **रात्रिचर्या** – सन्ध्याकाल के लिए उचित आचरण से रात्रिकाल में करणीय कर्म रात्रीचर्या के अन्तर्गत आते है। रात्रीचर्या के अन्तर्गत रात्री भोजन, शयन, निद्रा एवं स्वप्न ब्रह्मचर्यादि पालन आदि कर्म स्वस्थवृत्त सम्बन्धी रात्रीचर्या के अंग है।

अन्त में तत्वबोध- की साधना की जाती है। सोने से पहले तत्वबोध की साधना में दिन भर के कार्यों की समीक्षा की जाती है। भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना तथा सब कुछ प्रभु को सौंप कर स्वयं भी उसी की गोद में सो जाना चाहिए।

ऋतुचर्या दिनचर्या एवं रात्रिचर्या के सभी पालनीय नियमों का पालन करने के साथ साथ ऋतुचर्या का पालन करना अनिवार्य है। ऋतुचर्या अर्थात् ऋतुओं के अनुकूल आहार–विहार करना। ऋतुओं के लक्षणों को देखकर उनके अनुकूल आहार विहार का सेवन करने से मनुष्य सदा स्वस्थ रहता है। **(लेखिका आयुर्वेदाचार्या हैं)** ■

ISSN No. 2581-3528

उत्तर प्रदेश 2017 से पहले और बाद

	2017 से पहले	2017 के बाद
1.	2015-16 में उत्तर प्रदेश 10.9 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था	2020-21 में यह 19.4 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था
2.	2015-16 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय ₹47116 थी।	वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर ₹94495
3.	सनातन हिंदू धर्म के धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों की उपेक्षा	चार आध्यात्मिक परिपथ, विरासत परिपथ योजना से 100 पर्यटक स्थलों का विकास कार्य प्राथमिकता से
4.	तीर्थ स्थलों की दशा बदहाल, हज हॉउस जैसे प्रोजेक्ट से तुष्टिकरण का कार्य, सांस्कृतिक एवं एतिहासिक स्थलों के प्रति लापरवाही।	13 तीर्थ परिपथों के माध्यम से तीर्थों, सांस्कृतिक केन्द्रों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों को परस्पर जोड़ने की योजना।
5.	कुंभ का आयोजन अव्यवस्थाओं से भरा एक निपटाने वाला आयोजन	कुंभ को दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के साथ ही स्वच्छ कुंभ, सांस्कृतिक कुंभ, सुरक्षित कुंभ एवं डिजिटल कुंभ आदि की संभावना से जोड़ा गया
6.	अपराधी तत्वों को संरक्षण माफिया राज का बोलबाला था पुलिस अपराधियों के आगे बेबस, माफिया राज, कानून व्यवस्था चौपट	अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, माफिया तत्वों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई लगभग 1800 करोड रुपए मूल्य की संपत्ति ध्वस्त अथवा जब्त की, दुरुस्त कानून व्यवस्था
7.	2017 से पूर्व अपराधी खुले में घूमते थे और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था	विगत साढ़े चार वर्षों में 146 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और 3349 अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए, शेष जान बचाने को थाने में आकर करने लगे समर्पण
8.	प्रदेश के कुछ ही जनपदों में महिला हेल्प डेस्क	प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित
9.	अवैध निर्माण, सरकारी सम्पत्ति पर भू माफियाओं का कब्ज़ा	अवैध रूप से बनी माफियाओं की संपत्ति को धराशायी या जब्त किया, सरकारी भूमि कब्जामुक्त कराई गयी
10.	लड़कों से गलतियाँ हो जाती है कहकर बहन बेटियों से छेड़ छाड़ करने वालों को संरक्षण	एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना की गयी, बहन बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता, कोई समझौता नहीं
11.	लव जिहाद चरम पर, हिन्दू बहन बेटियों को धोखा देकर विवाह करना, मतान्तरण कराना बड़ी समस्या	लव जिहाद पर कानून बनाकर रोक लगी, धोखा देने वाले जा रहे हैं जेल
12.	संप्रदाय विशेष के उग्र दंगों में झुलसता प्रदेश (कोसींकला, कैराना, सहारनपुर)	पिछले साढ़े चार वर्षों में कोई भी दंगा नहीं, प्रदेश बना दंगामुक्त प्रदेश
13.	शिक्षा प्रणाली में शिक्षा माफियाओं का राज, प्राथमिक शिक्षा बदहाल, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार, बोर्ड परीक्षाएं दो से ढाई माह में, परीक्षाफल देरी से	शिक्षा मफिया पर नकेल कस नक़लविहीन परीक्षा, ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, बोर्ड परीक्षा को 1 माह में पूर्ण कराकर समय पर परीक्षाफल, भ्रष्टाचार पर लगाम
14.	'हमारी बेटी उसका कल' योजना के तहत केवल मुस्लिम लड़कियों को तीस हजार रुपये का उच्च शिक्षा अनुदान, हिन्दू बेटियों को नहीं दिया अनुदान	सबका साथ सबका विकास के तहत अनुदान की योजनायें हिन्दू मुस्लिम सभी के लिए, कोई भेद भाव नहीं
15.	2017 से पूर्व किसान सिंचाई के लिए सीमित संसाधनों और वर्षा पर ही निर्भर	सिंचाई के लिए अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूर्ण किया। बाणसागर परियोजना, अर्जुन सहायक बांध सहित कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। सरयू और मध्य गंगा नहर परियोजना भी पूर्णता की ओर।
16.	सूखे से प्रभावित विंध्य और बुंदेलखंड को हाशिये पर डालकर रखा गया।	सूखे से प्रभावित विंध्य और बुंदेलखंड में जल प्रबंधन पर जोर, नदियों को जोड़ने पर काम, किसानो को तालाब निर्माण हेतु अनुदान। अकेले बुंदेलखंड में साढ़े तीन हजार तालाब खोदे गए।
17.	विश्वविद्यालय राजनीति के अड्डे, पुराने ढर्रे पर विदेशी शिक्षा पद्धति का प्रभाव	विश्वविद्यालयों को भारत की अस्मिता से जोड़ने का कार्य, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना एवं भारत अध्ययन केन्द्र पर कार्य प्रगति पर

ISSN No. 2581-3528

18.	प्रत्येक मंडल में विश्वविद्यालय नहीं, शिक्षा के लिए दूर दराज जाने को मजबूर युवा वर्ग, गरीबों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन	7 विश्वविद्यालय एवं 50 महाविद्यालयों का कार्य प्रगति पर, प्रत्येक मंडल में राज्य विश्वविद्यालय, 35 नए राजकीय आईटीआई, 250 नए इंटर कॉलेज की स्थापना, 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किये ।
19.	प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज	प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज, चार वर्षों में 32 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर प्रदेश को चिकित्सा शिक्षा में अव्वल बनाया।
20.	नेतृत्व के जन्मदिन पर पैसों की उगाही, भौंडे कार्यक्रमों पर जनता का पैसा बर्बाद।	राष्ट्रनायकों एवं महापुरुषों के जन्म दिन मनाने पर बल, उनकी प्रतिमाओं की स्थापना
21.	1978 में पहचान लिए जाने के बावजूद इन्सेफेलाइटिस नामक जानलेवा बीमारी से पूर्वांचल के सैंकड़ों बच्चे कालग्रसित होते रहे	संकल्प के साथ इस बीमारी के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया, पूर्वांचल में बीमारी बड़ी सीमा तक नियंत्रण में
22.	महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था और कुशल प्रबंधन की कमी, आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकताओं से जूझता प्रदेश।	संकट बन अचानक आयी कोरोना महामारी से निपटने हेतु त्वरित गति से कार्य, प्रत्येक ब्लाक एवं जनपद स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त कर नव निर्मित किया। 14 करोड़ से अधिक टीकाकरण कर बना अव्वल प्रदेश।
23.	गरीबों के राशन की होती थी कालाबाजारी, भ्रष्ट व्यवस्था में जरूरतमंद को नहीं मिलता था राशन।	ऑनलाइन प्रणाली युक्त भ्रष्टाचार मुक्त विपणन से गरीबों को मिल रहा है फ्री गेहूं चावल तेल और चना
24.	गरीबों को उपचार हेतु भटकना पड़ता था।	चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ कर अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा।
25.	उत्तर प्रदेश के श्रमिक दूसरे राज्यों में जाकर आजीविकोपार्जन करने को मजबूर। प्रदेश में पर्याप्त रोजगार का अभाव	एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं से स्थानीय रोजगार को बढावा, करोना काल में लौटे श्रमिकों के लिए प्रदेश में ही रोजगार की संभावनाओं के द्वार खोलना। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला
26.	सार्वजानिक स्थलों पर असामाजिक लोगो द्वारा शराब का सेवन आम चलन	सार्वजानिक स्थानों पर शराब पीने पर 11,85,347 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी
27.	उग्र आंदोलनों एवं प्रदर्शन की आड़ में सरकारी और निजी संपत्ति को आग लगाना, तोड़ फोड़ करना भीड़ का काम, कोई कार्रवाई नहीं, अराजक तत्व सक्रिय	प्रदर्शन करने वालों को पहचान पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही और नुकसान की आर्थिक भरपाई भी, अराजकता पर लगा अंकुश, कोई नहीं करता दुस्साहस।
28.	24 करोड़ की आबादी, संसाधनों के साथ उपजाऊ भूमि फिर भी प्रदेश की गिनती पिछड़े प्रदेशों में	अपराधमुक्त वातावरण, निवेश की संभावनाओं से युक्त उद्यमिता एवं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता उन्नत प्रदेश
29.	भेदभाव के साथ कुछ जिलों को छोड़कर 8 से 12 घंटे की बिजली आपूर्ति , पॉवर परचेज एग्रीमेंट 5.14 रु प्रति यूनिट से 11.09 रु प्रति यूनिट किया गया, बिजली चोरी रोकने को पुख्ता इंतजाम नहीं।	सभी जिलों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति, पॉवर परचेज एग्रीमेंट 2.98 रु प्रति यूनिट से 4.19 रु प्रति यूनिट किया, बिजली चोरी रोकने हेतु 636 शहरों-कस्बों में 4,129 किलोमीटर तारों को भूमिगत किया।
30.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मामले लंबित, किसानों को नहीं मिलता था लाभ।	किसानों की 3 लाख 70 हजार 85 शिकायतों में से केवल 1158 मामले ही लंबित, शेष का हुआ निपटारा।
31.	भ्रष्ट व्यवस्था के चलते कृषि मंडियों की स्थिति दयनीय, अधिकांश घाटे में, मार्च 2017 में मंडी परिषद् की आय मात्र 1210 करोड़ रूपये	मंडी शुल्क एवं अन्य सुधारों के द्वारा वर्तमान में मंडी समितिया लाभ की स्थिति में, किसानों को आत्मनिर्भर बनने में दे रही महत्वपूर्ण योगदान। 2019-20 में आय बढ़कर हुई 1997 करोड़ रूपये।
32.	रक्षा क्षेत्र के उत्पादन हेतु कोई विशेष परियोजना नहीं	वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, झाँसी, आगरा, अलीगढ और चित्रकूट में 6 नोड से रक्षा गलियारों के निर्माण को हरी झंडी। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन में उत्तर प्रदेश भी देगा अहम योगदान।
33.	अव्यवस्थाओं के चलते 2014 में ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान 14 वां	प्रशासनिक सुधारों के चलते ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान पहुंचा देश में दूसरा

34.	आपराधिक छवि के चलते प्रदेश से बाहरी निवेशकों की निवेश में रुचि नहीं	प्रदेश की बदलती तस्वीर के चलते तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक का प्रदेश में निवेश, 68 कम्पनियां कर चुकी हैं अनुबंध।
35.	चीनी मिलो में किसानों के भुगतान का बकाया शेष	गन्ना किसानों को पिछले बकाया का 1.46 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान
36.	एक समुदाय विशेष के उत्पीडन के चलते कैराना से हिन्दुओं का पलायन	हालात सुधरे, लोगों का पलायन रुका, परिवार घर लौटे
37.	पैसों के लालच, भय और धोखे में रखकर मतान्तरण किया जाता था	मतान्तरण पर कानून बनाकर लगाई गयी रोक, लोग कर रहे घर वापसी
38.	2017 से पहले प्रदेश में किसानों से केवल गेहूं और धान की खरीद की जाती थी।	2017 में रिकॉर्ड खरीद करने के बाद प्रदेश सरकार हर वर्ष अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए उड़द और मूंग दाल की खरीद को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है
39.	घरेलू और व्यवसायी बिजली का कनेक्शन लेने में बिजली विभाग के कई चक्कर लगाने पड़ते थे	घरेलू और 20 किलो वाट तक के व्यावसायिक कनेक्शन देने के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन झटपट पोर्टल के जरिए अब तक 12 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं
40.	2012 से 2017 तक केवल 47.75 लाख घरों में बिजली पहुंची।	2017 से 2021 के बीच 1 करोड़ चालीस लाख घरों को बिजली के नए कनेक्शन मिले।
41.	पिछली सरकार में प्रतिवर्ष 20000 से भी कम ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाते थे।	अब किसानो को प्रतिवर्ष 34194 कनेक्शन मिल रहे हैं।
42.	भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर उठाये जाते थे सवाल।	विरोध करने वाले भी श्री राम और श्री कृष्ण के सामने झुका रहे अपना सिर।
43.	बेटियों के बाहर निकलने के समय पर उठाये जाते थे सवाल, छोटी उम्र में ही कर दिया जाता था विवाह	कन्याओं को आगे पढ़ने और बढ़ने के अवसर देने हेतु विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की
44.	आर्थिक रूप से पुरुषों पर आश्रित थीं महिलाएं।	1,60,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दो लाख महिलाओं के खाते में 1,000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व पहल।
45.	आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया जाता था, उन्हें पनाह मिलती थी।	आतंकवादियों के सफाए के लिए ATS स्थापित किये जा रहे हैं।
46.	वेक्सीन और सेना पर सवाल उठाकर देश का किया अपमान, लोगों को गुमराह किया।	भारतीय वेक्सीन मिली अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति, सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ा देश का मान।
47.	वोट के लिए जिन्ना जैसे देशघातियों को देते हैं सम्मान, उनके लिए देश नहीं सत्ता है जरुरी	देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों का होता सम्मान, देशघातियों का नहीं कोई स्थान
48.	हिन्दू, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का विरोध ही है जिनका मुख्य एजेंडा	सबका साथ सबका विकास लिए हिन्दू, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति ही जिनके लिए है सर्वोपरि
49.	ये गोल जालीदार टोपी तो पहन लेते थे लेकिन मंदिर जाने में शर्म आती थी। चुनाव आते ही बदल लेते हैं रंग।	तुष्टिकरण की नीति नहीं, सबका साथ सबका विकास
50.	प्रदेश में एकमात्र एक्सप्रेस वे, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, परिवहन से पिछड़ा तो विकास से पिछड़ा।	प्रदेश बन रहा है 5 एक्सप्रेसवे वाला, एक लोकार्पित , 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे , 2 लोकार्पित। परिवहन व्यवस्था के उन्नत होने से उन्नत हो रहा प्रदेश।

संयोजन – डॉ. निर्भय प्रताप सिंह

पत्रिका के जनवरी अंक की समीक्षा

डॉ. प्रियंका सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
शम्भू दयाल पीजी कॉलेज, गाजियाबाद

आंदोलन अन्याय के खिलाफ किया गया एक सामूहिक संघर्ष होता है जो संगठित व्यवस्थित और अनुशासित होता है परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब जन आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित, पूर्ण नियोजित होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जन भावनाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ किसान आंदोलन रहा जिसमें किसान व आंदोलन दोनों की छवि धूमिल की है। इसी विषय की धरातली सच्चाई को इस अंक के माध्यम से सुधी पाठकों के समक्ष बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लाने का प्रयास है जिसमें पहला लेख किसने छिपाया किसान आंदोलन का सच में आदरणीय बलबीर जी लिखते है कि विगत एक वर्ष से जारी उपद्रव और संबंधित गतिविधियों की मीडिया का एक समूह जो मार्क्स मैकाले चिंतन के निकट अधिक दिखता है और आज भी सार्वजनिक विमर्श को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता रखता है उसने इस अराजकता को किसान आंदोलन की संज्ञा दे दी। वहीं पद्मश्री विष्णु पंडया जी 'आंदोलन कुछ सही कुछ गलत' में लिखते हैं कि आंदोलन का अस्तित्व असंतोष या अन्याय के विरुद्ध है ना कि निहित स्वार्थ के लिए। जैसे किसान आंदोलन, शाहीन बाग और कुछ निरर्थक आंदोलन जो कभी संसद में और कभी संसद के बाहर प्रदर्शन, सभी तथाकथित अन्याय के खिलाफ और तथाकथित लोकतंत्र को बचाने के लिए और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाया है श्री रतन शारदा जी ने जिसमें वह भी लिखते हैं कि आंदोलन के पीछे अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं जिनके इशारों पर और उनके साधनों के सहारे राजनैतिक अस्थिरता के लिए किए जाते हैं। रंजना मिश्रा जी ने अपने लेख के माध्यम से आमजन को संविधान को जानने व समझने का आवाहन किया है। वे लिखती हैं कि गीता का सार हम सभी को पता है परंतु संविधान का सार कुछ लोगों को ही पता है जो है 'स्वतंत्रता, समानता और न्याय ही हमारे शासन का आधार है'। श्रीमती अनुपमा अग्रवाल जी ने सेवा कार्यों में समर्पित यूथ यूनीटेल वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था जिसे गोरखपुर में युवा इंडिया के नाम से जाना जाता है इसके संस्थापक रत्नेश कुमार तिवारी जी के समर्पण भाव पर प्रकाश डाला है। जिनका ध्येय मूलभूत सुविधाओं से वंचित बस्तियों में शिक्षा का अलख जगाना है। प्रो. हरेंद्र जी ने 'हमारी धरोहर हमारी काशी' की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है। वही प्रो. अखिलेश मिश्र जी ने अपने लेख 'आर्थिक विकास में मीडिया एवं आंदोलन की भूमिका' पर कई प्रश्न खड़े किए है। प्रो. अनिल कुमार निगम जी अपने लेख में लिखते हैं कि मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में एक दिशा निर्देशक की भूमिका निभाएगा। डॉ. नीलम कुमारी जी का लेख भारतीय महिला गणितज्ञ नीना गुप्ता जी को समर्पित है। सुनील आंबेकर जी की पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र' की समीक्षा की है डॉ. प्रदीप कुमार जी ने। अश्विनी उपाध्याय जी ने लोकतांत्रिक आंदोलन और न्यायपालिका की भूमिका पर बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपने मत रखे। अखंड भारत का वृहद स्वरूप पर डॉ हेमेन्द्र कुमार राजपूत जी का लेख है। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान करने का अपने लेख के माध्यम से स्वागत किया है प्रमोद भार्गव जी ने और इसके दूसरे पक्ष पर भी उन्होंने चर्चा की है। उत्सव मंथन लेख के माध्यम से नीलम भागी जी ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के कई रंग दिखाएं। 'घातक है आंदोलनों में निवेशकों की बढ़ती भूमिका और कम होती पारदर्शिता' विषय पर आशीष कुमार अंशु जी लिखते हैं कि आंदोलनों के रूप में शुरू हुई परंपरा बेहद खतरनाक है। भारत में आंदोलनों के इतिहास पर प्रतीक खरे जी ने विश्लेषण किया है। 'बाला साहब देवरस- व्यायामशाला से सरसंघचालक का सफर' विषय पर अपने भाव व्यक्त किए हैं मोहित कुमार जी ने। अंत में मीडिया सुर्खियों का संयोजन प्रतीक खरे जी के द्वारा किया गया है और दिसंबर अंक की समीक्षा डॉ प्रियंका सिंह जी के द्वारा की गई है। आशा करती हूं कि यह पत्रिका सुधि पाठकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।

पत्रिका का विमोचन आदरणीय बलबीर जी पुंज एवं आदरणीय रतन शारदा जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया।

प्रेरणा विमर्श 2020 के अवसर पर केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक सिने विमर्श और भारतीय विरासत का विमोचन करते लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिडला जी, गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक अन्त्योदय की ओर का विमोचन करते सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वरिष्ठ लेखिका अद्वैता काला जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक पत्रकारिता के अग्रदूत का विमोचन करते उत्तर प्रदेश के मा.राज्यपाल श्री राम नाईक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघचालक श्री सूर्यप्रकाश टोंक जी, माखनलाल चतुर्वेदी विवि. के पूर्व कुलपति श्री जगदीश उपासने जी व अन्य अतिथिगण